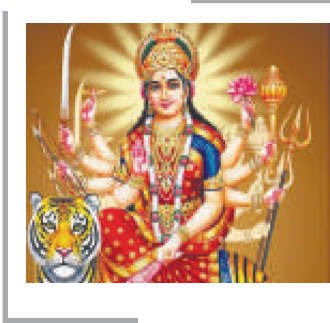




राहुल का अहंकार ले डूबा संसद का मानसून सत्र: रविशंकर

नईदिल्ली। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र के बेकार जाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अहंकार, जिद और हक जताने की सोच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार होने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के अहंकार और पूरी तरह से अनुशासनहीनता की वजह से संसद का पूरा सत्र बर्बाद हो गया।

प्रसाद ने कहा कि संसद का पूरा मॉनसून सत्र एक नेता के अहंकार, अनुशासन की कमी और जिद की भेंट चढ़ गया। मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। संसद का पूरा मॉनसून सत्र विपक्ष के नेता के अहंकार, मनमानी, हक जताने की सोच और पूरी



तरह से अनुशासनहीनता की भेंट चढ़ गया। प्रसाद ने बताया कि शाह ने पुलिस की कार्रवाई पर बहस में शामिल होने और विपक्ष की सभी दलीलों का जवाब देने की पेशकश की थी।

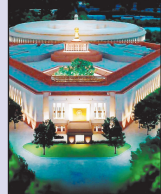
उन्होंने कहा कि कल आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री खुद मीडिया के सामने आए और कहा, मैं पूरी बहस सुनने और पुलिस से जुड़ी घटनाओं पर उनकी सभी दलीलों का जवाब देने के लिए 24 घंटे तक बैठने को तैयार हूँ। मैं हर एक बात का जवाब दूँगा। हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और सदन में यह बात उठाई कि हम बहस के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के शाह के इस्तीफे की मांग

वाले बयानों की आलोचना करते हुए, प्रसाद ने पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठाए। प्रसाद ने कहा कि लेकिन फिर उनके दो बेवकूफी भर बयान आए, जिन्हें मैं कोट करना चाहूंगा अगर उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया। तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वह एक अक्षम और बेकार मंत्री हैं, इसलिए उन्हें फिर भी इस्तीफा देना चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी, क्या आपको गवर्नेंस की बुनियादी समझ भी नहीं है? क्या गृह मंत्री कभी फायरिंग का आदेश देते हैं? इसका क्या मतलब है? इसके लिए नियम हैं; एक प्रोटोकॉल है। वहां मौजूद मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी, या डिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस--उनसे सलाह लेने के बाद ही कार्रवाई की जाती है।

लोकसभा में 19त राज्यसभा में 39.17त हो सका कामकाज

मानसून सत्र जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी, नीट पेपर लोक और अमित शाह के सदन नहीं आने के मुद्दे पर खासा हंगामेदार रहा। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुल 37 घंटे, 49 मिनट ही काम हुआ। इस दौरान 12 विधेयकों पर चर्चा और पारित किया गया। आखिरी दिन भी खान और खनिज संशोधन विधेयक को राज्यसभा से पारित कराया गया। लोकसभा में भी मानसून सत्र के दौरान 11 विधेयक पेश या पारित कराए गए। इनमें सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, केरल का नाम बदलने वाला विधेयक भी शामिल है।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज कोई काम नहीं हुआ और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में आते ही सदस्यों से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने की अपील की। इसके बाद लोकसभा में वंदे मातरम का गायन हुआ और इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्थगित होने के बाद भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सप्ता सांसदों ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सप्ता सांसद धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ सांसदों ने तय किया है कि वे कनाट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे। अब भगवान हनुमान ही भगवान राम के चंदे की सुरक्षा कर सकेंगे। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि %सरकार सदन चलवाने में असफल रही। सदन तभी चलता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बातचीत करें और सदन चलाने का रास्ता ढूँढ़ें।



रायपुर। तिरंगा यात्रा के दूसरे दिवस उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने माँ दत्तेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात दत्तेवाड़ा बस स्टैंड में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दत्तेवाड़ा जिले के 211 सर्वोच्च बलिदानी वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि बस्तर की जनता, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के अमूल्य सहयोग से आज नक्सलवाद का खात्मा संभव हुआ है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आमजनों से अपने घरों में तिरंगा लगाने तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता निभाने की अपील की।

इधर डिफेंस डील, उधर इजरायल ने तुर्की-पाक को ठोका



नईदिल्ली। एक तरफ जहां पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने आपस में गठबंधन किया, डिफेंस डील किया और शेखी बचारी तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि मोर्चा खोल दिया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जहां ट्वीट करके तुर्कियों पर यह आरोप लगाया है कि तुर्की लगातार आतंकी संगठन हमास को फलने फूलने की जगह दे रहा है तो दूसरी तरफ जो तुर्की का दूतावास भारत में मौजूद है। हमास का फुटप्रिंट अब पाकिस्तान में खूब बढ़ रहा है और यह चिंता का कारण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुर्की पर लगे आरोप की। तो इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए

लिखा है कि तुर्की एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने के बजाय जिहादी हमास को पनाह दे रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास अपनी ज्यादातर गुप्त गतिविधियां जिसमें प्लानिंग साइबर ऑपरेशन शामिल है उसको तुर्की के इलाके में ले जा रहा है।

जो देश आतंकवादियों को प्लानिंग संगठन बनाने लोगों को भर्ती करने की जगह देता है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस पूरे मामले पर जो कान है उसकी एक रिपोर्ट भी सामने है। उसमें कहा गया है कि हमास अपनी कुछ संगठनात्मक गतिविधियां जिसमें प्लानिंग साइबर विभाग शामिल है उसे तुर्की शिफ्ट कर रहा है। फिलिस्तीनी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तुर्की में ट्रांसफर होने वाली गतिविधियों में हमास की ज्यादातर गुप्त गतिविधियां शामिल हैं। जबकि कतर इस आतंकवादी संगठन के नेतृत्व और सार्वजनिक गतिविधियों की मेजबानी करता रहेगा।

12 पुलिस अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित करने की घोषणा की थी। उक्त राष्ट्रपति पदक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान करेंगे। भौगोलिकसंदर्भ

इनको मिलेगा पदक: विशिष्ट सेवाओं के लिए रामावतार सिंह राजपुत सहायक उप निरीक्षक, रक्षित केंद्र जिला धमतरी को राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए पदक रामगोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, शशिमोहन सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़, श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण, राजश्री मिश्रा पुलिस अधीक्षक एटीएस, विशा पुलिस मुख्यालय रायपुर, निवेदिता पाल सेनानी 6वीं वाहिनी छसबले रायगढ़, मनीषा ठाकुर रावटे सेनानी 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद, तारकेश्वर पटेल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस मध्य पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय, उमैजा खातून अंसारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विआशा पुलिस मुख्यालय रायपुर, जयलाल मरकाम सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई, हजारी लाल साहू, प्लाटून कमांडर, 20वीं वाहिनी छसबल महासमुंद को प्रदान किया जाएगा।

भाजपा थोप रही अपना सिस्टम: राहुल

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नीट-यूजी पेपर लोक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। नई दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीतिक विचारधारा भारत पर ऐसी व्यवस्था थोपना है जिससे उन्हें और कुछ खास लोगों को फायदा हो। उन्होंने कहा, हमारा काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना है।सम्मेलन में बातचीत के अंदाज में अपनी बात रखते हुए गांधी ने जोर दिया कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी द्वारा थोपी



गई व्यवस्था को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जो हो रहा था, वह यह है कि छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं। वे परेशान हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है—नहीं। हम जंतर-मंतर पर व्यवस्था कायम करेंगे। आप अपनी बात नहीं रख सकते।

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने विरोध-प्रदर्शन के हालात की तुलना एक रेप पीड़िता के परिवार के साथ हुई अपनी बातचीत से की।उन्होंने याद करते हुए कहा कि आज एक महिला मेरे पास आई, जिसकी बेटी के साथ चार साल पहले उत्तराखंड में रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी।

गई व्यवस्था को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जो हो रहा था, वह यह है कि छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं। वे परेशान हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है—नहीं। हम जंतर-मंतर पर व्यवस्था कायम करेंगे। आप अपनी बात नहीं रख सकते।

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने विरोध-प्रदर्शन के हालात की तुलना एक रेप पीड़िता के परिवार के साथ हुई अपनी बातचीत से की।उन्होंने याद करते हुए कहा कि आज एक महिला मेरे पास आई, जिसकी बेटी के साथ चार साल पहले उत्तराखंड में रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी।

प्रमुख समाचार

लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी से विपक्ष ने किया बहिष्कार

नईदिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद, गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया। सूत्रों के मुताबिक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नेता कनिमोड़ी इस पारंपरिक मिलन-समारोह में शामिल हुईं। राज्यसभा में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने चैयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा आयोजित चाय पार्टी में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हुई चाय पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों के नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चैयरमैन-अपने-अपने चैंबर में चाय पार्टी का आयोजन करते हैं।

कनिमोड़ी की चाय पर चर्चा ने खोले नए सियासी रास्ते

नईदिल्ली। इस बात का एक और संकेत कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) विवादित परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है, पार्टी की लोकसभा सदस्य कनिमोड़ी करुणानिधि ने गुरुवार को स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गई चाय-पे-चर्चा में हिस्सा लिया। यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र के समापन और निचले सदन (लोकसभा) की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद आयोजित की गई थी। विपक्ष की ओर से कनिमोड़ी ही एकमात्र ऐसी नेता थीं जिन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य नेताओं के दूर रहने के बावजूद कनिमोड़ी का पारंपरिक चाय-बैठक में शामिल होना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनकी पार्टी परिसीमन (डिलिमिटेशन) का समर्थन करने पर विचार कर रही है; यह प्रस्ताव अप्रैल में हुए विशेष सत्र के दौरान लोकसभा से पारित नहीं हो पाया था। अप्रैल में जब परिसीमन बिल पेश किया गया था, तो छत्ती ने इसका जोरदार विरोध किया था।

12 बिल पास, पर बहस और चर्चा न होने से दुखी : रिजिजू

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि संसद का हाल ही में खत्म हुआ मॉनसून सत्र विधायी नज़रिए से सफल रहा, जिसमें 12 बिल पास हुए, लेकिन उन्होंने माना कि बहस और चर्चा के मामले में यह सत्र उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। सत्र खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने इस सत्र का आकलन दो अलग-अलग नज़रियों से किया। जहाँ विधायी कामकाज योजना के मुताबिक अगर बढ़ा, वहीं दोनों सदनों में हुए हंगामे ने कुल कामकाज पर असर डाला। रिजिजू ने कहा कि कुल 12 बिल पास हुए, लेकिन हम चर्चा की क्वालिटी से खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष ने ठीक से बहस नहीं होने दी, खासकर लोकसभा में। मैंने पहली बार देखा है कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है। विपक्ष सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। फिर भी, संसद के अंदर हमने देखा कि सरकार खुद चर्चा चाहती थी, जबकि विपक्ष उससे बचने के लिए बहाने बना रहा था।

खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण पर बवाल

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने 13 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद भाजपा और आरएसएस द्वारा किए गए शुद्धिकरण हवन की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस कार्यक्रम की निंदा करने और माफ़ी मांगने की मांग की। खरगे ने 8 अगस्त को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत कांग्रेस की रैली में भाषण दिया। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सोच साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को दिखाती है। प्रधानमंत्री को इसकी निंदा करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी भाजपा और आरएसएस की आलोचना की और सत्ताधारी पार्टी पर ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जो समानता के खिलाफ है। भाजपा-आरएसएस सरकार और उनकी विचारधारा के लिए यह शर्म की बात है। कि एक तरफ तो वे तिरंगा यात्रा निकालने और ऐसी पब्लिसिटी करने की बात करते हैं।

खड़गे के आरोप के बाद जेपी नड्डा ने कार्रवाई का वादा किया

नईदिल्ली। राज्यसभा में फिर से हंगामा हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में उनकी रैली के बाद एक शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। खड़गे के आरोपों के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कार्रवाई का वादा किया, लेकिन राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। राज्यसभा में सदन के नेता नड्डा ने कहा कि जो हुआ उससे उन्हें भी दुख हुआ है, लेकिन इस मुद्दे को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी का बचाव भी किया और कहा कि भगवा पार्टी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। हालाँकि, अगर खड़गे जी इसके लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है। जिसने भी ऐसा किया है, वह गलत है। इसे सनसनीखेज न बनाएं। मुझे भी इसका दुख है। हम इसकी विस्तार से जांच करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसका राजनीतिकरण न करें।

एमएसएमई तंत्र को मजबूत करने के लिए सुधारों का अगला चरण

जीतन राम मांझी

संसद के दोनों सदनों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का पारित होना, एमएसएमई के लिए भारत के कानूनी ढांचे को तेजी से बदलते तंत्र के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मूल अधिनियम के बाद से पिछले दो दशकों में, लाखों उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं और एमएसएमई राष्ट्रीय विकास, निर्यात और रोजगार सृजन में अहम योगदान देने वाले बन गए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य एमएसएमई इकोसिस्टम को ज्यादा संवेदशील और भरोसे पर आधारित बनाना है। इससे पंजीकरण आसान होगा, वर्गीकरण बेहतर होगा, ऋण तक पहुंच और समय पर भुगतान आसान होगा, विवादों का

निपटारा डिजिटल और तेज होगा और नियमों का पालन आसान होगा। इस संशोधन में उद्यमों के मुफ्त और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान किया गया है। इससे कई तरह की बाधाएं दूर होंगी और सरकार को बेहतर तरीके से लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अधिनियम के तहत पंजीकरण एक पात्रता है, जिसका दावा कोई भी कंपनी कर सकती है, यह कोई बाध्यता नहीं है। यह संशोधन संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में निवेश और कारोबार के संयुक्त मानदंडों के आधार पर उद्यमों के वर्गीकरण के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस वर्गीकरण से फ्रेमवर्क को प्रौद्योगिकी, लागत, बाजार और व्यवसाय मॉडल में आने वाले बदलावों के अनुसार तेजी से ढाला सकता है और यह केंद्र सरकार को

रसीद (इनवॉइस) के भुगतान और जानकारी देने को अनिवार्य बनाकर पारदर्शिता लाता है। राज्य सरकारें भी यह नियम अपने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते, xस39;ट्रेड्सxस39; एक स्वीकृत इनवॉइस के आधार पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से तुरंत वित्तपोषण प्राप्त

करने की सुविधा देता है। इससे आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान मिल जाता है, जबकि खरीदार तय तिथि पर बैंक या वित्तीय संस्थान को भुगतान चुकता करता है। इस प्रकार, रिसिवेबल्स (मिलने वाली रकम) आपूर्तिकर्ता के लिए लिक्विडिटी का जरिया बन जाता है, जिससे कंपनी को अपने कामकाज का प्रबंधन करने, बिलों का भुगतान करने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आसानी होती है। समाधान यह इस अधिनियम के विवाद-समाधान फ्रेमवर्क को और अधिक मजबूत करता है। यह राज्य सरकारों को मध्यस्थता और सुलह के लिए अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिपदों (एमएसइएफसी) की स्थापना करने में सक्षम बनाता है। यह मध्यस्थता और

सुलह के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है तथा ऑनलाइन विवाद-समाधान को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इससे मामलों का तेजी से निपटारा होगा और एक ऐसी व्यवस्था तैयार होगी जिससे कंपनी प्रक्रिया और समय-सीमा की निश्चितता के साथ अपने जायज़ दावों को पेश कर सकेगी।

कार्यान्वयन सुविधा परिपदों द्वारा दिए गए निर्णय के तहत मिलने वाली रकम को ज़मीन के लगान की बकाया राशि की तरह वसूला जा सकता है। यदि कोई खरीदार किसी फैसले को अदालत में चुनौती देना चाहता है, तो उसे तय राशि का 75 प्रतिशत अदालत में जमा करना होगा और यदि वह चुनौती छल लघु उद्यम सुविधा परिपदों (एमएसइएफसी) की स्थापना करने में सक्षम बनाता है। यह मध्यस्थता और

प्रकार, लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण जायज दावों को खारिज नहीं किया जा सकेगा और अदालत में बीतने वाला समय अब केवल खरीदार के पक्ष में नहीं होगा। यह संशोधन उद्यमों के लिए अनुपालन के प्रति अधिक संतुलित और विश्वास-आधारित दृष्टिकोण की दिशा में बदलाव को भी दर्शाता है। छोटे-मोटे उल्लंघन के लिए अब पहली बार में केवल चेतावनी दी जाएगी और अपराध दोहराए जाने पर अलग-अलग आर्थिक जुर्माने लगाए जा सकते हैं। नियमों के पालन की प्रक्रिया को ज्यादा अनुमान लगाने लायक और आसान बनाकर, कंपनियाँ अब अपनी ऊर्जा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर लगा सकती हैं। इससे व्यवसाय करने में सुगमता (ईजु ऑफ़ डूइंग बिजनेस) और विश्वास-आधारित शासनको बढ़ावा मिलेगा।

स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह का हुआ फाइनल रिहर्सल, कलेक्टर-एसपी ने किया निरीक्षण

अपर कलेक्टर सुनील नायक ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई, ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी

अम्बिकापुर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के गरिमामय एवं व्यवस्थित आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पीजी कॉलेज ग्राउंड, अम्बिकापुर में मुख्य समारोह का फाइनल रिहर्सल आयोजित किया गया। कलेक्टर अजीत वसंत एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण कर समारोह स्थल पर की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिहर्सल के दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए अपर कलेक्टर सुनील नायक ने ध्वजारोहण किया तथा परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस एवं एनसीसी कैडेट्स सहित विभिन्न दलों ने अनुशासित एवं आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। फाइनल रिहर्सल के दौरान परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्रीमती तुषि सिंह राजपूत तथा सेकंड इन परेड कमांडर प्रशिक्षु सुश्री पवित्र वर्मा के नेतृत्व में कुल 13 प्लाटूनों ने परेड का प्रदर्शन किया। इसमें जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून के कमांडर प्रशिक्षु उप निरीक्षक डिगेश्वर वर्मा, जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून के कमांडर प्रशिक्षु उप निरीक्षक विवेक चंद्राकर, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून की कमांडर प्रशिक्षु उप निरीक्षक सुश्री भारती मार्कण्डेय, नगर सैनिक बल पुरुष प्लाटून के



कमांडर प्रशिक्षु उप निरीक्षक महेश कुमार नेताम तथा नगर सैनिक बल महिला प्लाटून की कमांडर प्रशिक्षु उप निरीक्षक सुश्री आशी झा शामिल रहीं। इसी प्रकार नव आरक्षक दल महिला-पुरुष संयुक्त के कमांडर नव आरक्षक 1006 समीर तिग्गा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर एनसीसी पुरुष के जेयूओ श्रेयांश कुमार, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर एनसीसी महिला के जेयूओ सुश्री प्रिंसी तिग्गा, होली क्रॉस वूमेन्स कॉलेज एनसीसी की एसयूओ सुश्री कुनूर, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर जूनियर डिविजन एनसीसी के श्री उपेन्द्र

राजवाड़े, सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर स्काउट के रोहित केरकेट्टा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाइड्स की कुमारी आस्था गुप्ता तथा अम्बिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरनीबेड़ा की कुमारी मोनिका मिंज के नेतृत्व में विभिन्न दलों ने परेड का फाइनल रिहर्सल किया। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस जवानों एवं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा पीटी परेड का प्रदर्शन किया जाएगा। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत

करेंगे। नवोदय, कार्मेल स्कूल, हॉलीक्रॉस स्कूल, मोंटफॉर्ट, उसू लाइन एवं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी देशभक्ति गीत, नृत्य एवं नाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति देंगे।समारोह के दौरान शहीद वीर जवानों के परिवारों तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा। इससे समारोह में देशभक्ति, सम्मान और गौरव की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह 15 अगस्त 2026 को पीजी कॉलेज ग्राउंड, अम्बिकापुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने समारोह स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह का गरिमामय एवं व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, साउंड सिस्टम, बेरिकेटिंग, पेयजल, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ग्राम करजी में आज से नशामुक्ति पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी

अम्बिकापुर। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान’ के अंतर्गत सरगुजा जिले के ग्राम करजी, विकासखंड अंबिकापुर में 14 और 15 अगस्त 2026 को नशामुक्ति पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन 14 अगस्त को अंबिकापुर विधायक श्री प्रबोध मिंज करेंगे। इस अवसर पर सीतापुर विधायक श्री राम कुमार टोणो, अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुषा सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक श्री रितेश चैधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन के बाद अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। दो दिवसीय प्रदर्शनी में चित्रों, इन्फोग्राफिक्स और अन्य दृश्य माध्यमों के जरिए नशीले पदार्थों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शनी में नशीले पदार्थों की पहचान, उनके शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति के कारण, शुद्धआती संकेत तथा ‘किफक बनाम तथ्य’ के माध्यम से नशे से जुड़ी भ्रांतियों की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, मानसिक तनाव, पारिवारिक विघटन, आर्थिक नुकसान, अपराध और सड़क दुर्घटनाओं जैसे नशे के दुष्परिणामों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरों का आतंक



एमसीबी। कोयलांचल नगरी चिरमिरी स्थित एसईसीएल की ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से कबाड़ से लदी एक स्कॉर्पियो को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसमें सवार कबाड़ माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना ने एक बार फिर खदान की सुरक्षा व्यवस्था और करोड़ों रुपये के सरकारी कबाड़ को सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस परिसर में बीती रात सुरक्षा कर्मियों को एक स्कॉर्पियो वाहन संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। वाहन पूरी तरह कबाड़ से लदा हुआ था।

कबाड़ माफिया स्कॉर्पियो जैसे वाहनों का इस्तेमाल कर खदान से लोहे, मशीनों के पुर्जें

और अन्य कबाड़ बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरा देख स्कॉर्पियो में सवार लोग वाहन को मौके पर ही छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। अंधेरे और खदान के दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर आरोपी फरार होने में सफल रहे। ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरी की घटनाएं कोई नई नहीं हैं।

लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि कबाड़ माफिया रात के समय खदान परिसर में घुसकर कीमती कबाड़ चोरी कर ले जाते हैं। अनुमान है कि इस तरह की चोरियां से एसईसीएल को हर महीने लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। कबाड़ को खुले बाजार में खपाकर माफिया मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इधर घटना की

सूचना मिलते ही एसईसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के उप क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी चिरमिरी पुलिस को दी।

सूचना पर चिरमिरी थाना प्रभारी विजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कबाड़ से लदी स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कबाड़ चोरी के पीछे कौन लोग शामिल हैं और खदान से चोरी किए गए कबाड़ को कहाँ खपाया जा रहा था।

वहीं माइंस के उप क्षेत्रीय प्रबंधक ने आगे कहा कि खदान में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हमारे सुरक्षकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए रंगे हाथ गाड़ी को कबाड़ चोरी करते पकड़ा है। इसकी जांच की जा रही है—अरुण सिंह चौहान, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस ओपन कास्ट माइंस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

महुआ शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 15 अगस्त से पहले अवैध शराब के खिलाफ आबकारी उड़नदस्ता की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने महुआ शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में महुआ शराब और लाहन जब्त किया गया है। भौगोलिकसंदर्भ यह पूरा मामला अंबिकापुर शहर के पटपरिया इलाके का है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए टीम ने किराए के मकान में छापेमारी की, जहां महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। मौके से 70 लीटर महुआ शराब और 480 किलो महुआ लाहन बरामद हुआ। एक कमरे में 8 भट्टियों पर शराब बनाने का काम चल रहा था, तो दूसरे कमरे में 24 प्लास्टिक डिब्बों में महुआ लाहन रखा था। इसी के साथ ही आबकारी उड़नदस्ता की टीम ने आरोपी अर्जुन कुचुर को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है

पुल की समस्या:जान जोखिम में डालकर बच्चे पार कर रहे सजाहिया नाला, अफसर मंत्री भी नहीं सुन रहे गुहार

जनपद पंचायत खड़गावां का ग्राम पंचायत सलका इन दिनों पुल की समस्या से जूझ रहा है

एमसीबी। जनपद पंचायत खड़गावां के ग्राम पंचायत सलका के हरिजनपारा से तेंदुदांड के बीच बहने वाला सजाहिया नाला ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुका है। नाले में पुल नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में ये नाला गांवों को दो टापुओं में बदल देता है। लिहाजा स्कूल जाने वाले बच्चे उफनते नाले को पार करने का जोखिम उठाते हैं। जिस मार्ग में ये नाला पड़ता है वो मार्ग सलका और मंगोरा पंचायतों को आपस में जोड़ता है।ग्रामीण कई साल से पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। आज भी सड़क के बीच बना ये नाला लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक बार पैर फिसला तो बहाव में बहने की पूरी आशंका है।

अभिभावक हर सुबह बच्चों को नाले तक छोड़ने जाते हैं और लौटने तक चिंता में रहते हैं। सजाहिया नाला पहले भी कई हादसों का गवाह बन चुका है। तेज बहाव में मवेशियों के बहने की घटनाएं इस गांव के लिए आम



बात हैं। पिछले साल नाले के तेज बहाव में एक वृद्ध महिला भी बह गई थी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं खुली। वहीं ग्रामीण सुनील कुमार ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार में विधायक ने पुलिया निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान मंत्री से भी 5-6 बार मुलाकात हो चुकी है। छह माह में काम पूरा होने की बात कही गई थी। बारिश में सड़क खराब होने से बच्चे

स्कूल नहीं जा पाते। मवेशियों के बहने की घटनाएं भी हुई हैं। उन्होंने पुलिया निर्माण की मांग की।वहीं गांव के सरपंच धनीराम पोते ने बताया कि इस बड़े नाले के निर्माण को लेकर कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं। यहां छोटे-छोटे बच्चे भी रोज आते-जाते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। नाला बड़ा होने के कारण पंचायत स्तर से पुलिया बनाना संभव नहीं है। अधिकारियों और मंत्री को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ- धनीराम

पोते, सरपंच गांव के रास्ते में नाला के कारण समस्या पैदा हो रही है। हमने आरएसएस विभाग को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया है कि मौके का परीक्षण कर आवश्यक स्टोमेट तैयार कर प्रस्तुत करें। आपको बता दें कि सजाहिया नाला आज सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है। बल्कि ये प्रशासनिक उदासीनता और अधूरे वादों की निशानी बन चुका है। एक तरफ नन्हे हाथों में किताबें हैं तो दूसरी तरफ उफनता नाला उनकी भविष्य की तैयारियों पर पानी फेरने के लिए खड़ा है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

स्वतंत्रता कप में दिखेगा खेल भावना और सौहार्द का उत्सव

धमतरी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपसी सद्भाव, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्वतंत्रता कप 2026’ का आयोजन 14 अगस्त को किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रशासन, मीडिया, वित्तीय एवं कर विभाग सहित विभिन्न संस्थानों की टीमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लेंगी। आयोजन का उद्देश्य खेल के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, आत्मीयता और सौहार्द को और मजबूत करना है। प्रतियोगिता के रूपा ए में सीए चैलेंजर्स, मीडिया मावेरिक्स, जीएफटी टाइटन्स और प्रशासनिक रॉयल्स (एडमिनिस्ट्रेटिव रॉयल्स) तथा रूपा बी में आईटीबीए एवेंजर्स, डीएफओ डेयरडेविल्स, मेयर किंग्स और आयकर अधिकारी सितारे शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी (महिला) एवं नगर निगम पार्षद (महिला) के बीच सद्भावना मैच भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजन नए क्रिकेट बाक्स में होगा । लोग मुकाबलों की शुरुआत शाम 5 बजे आईटीबीए एवेंजर्स बनाम डीएफओ डेयरडेविल्स से होगी।

जशपुर में मोबाइल दुकान से 40 लाख के मोबाइल चोरी

जशपुर। कुनकुरी के जयस्तंभ चौक के पास स्थित मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 40 लाख रुपए कीमत के मोबाइल हैंडसेट पार कर दिए। चोरों ने दुकान का दरवाजा और शटर पर लगे दोनों तालों को तोड़ा और अंदर रखे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। दुकान संचालक पंकज कुमार पारिक ने कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त की रात दुकान बंद करने के बाद वह हमेशा की तरह घर चले गए थे। 12 अगस्त पहुंचे तो शटर खुला हुआ था। पास जाकर देखने पर दोनों ताले टूटे मिले।दुकान के आसपास कटर समेत ताले तोड़ने में इस्तेमाल किए गए सामान भी पड़े थे। इसके बाद अंदर जाकर देखने पर मोबाइल फोन अस्त-व्यस्त मिले और कई हैंडसेट गायब थे। संचालक के अनुसार चोरी गए मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा का शुभारंभ

बिलासपुर। रेल यात्रियों की सुविधा और बेहतर स्थानीय परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बाइक रेंटल सेवा शुरू की गई है। स्टेशन के कोच रेस्टोरेंट के पास उपलब्ध इस सुविधा का शुभारंभ बुधवार को प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विजय कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह सहित वाणिज्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा है, जिसे यात्रियों को स्टेशन से शहर के विभिन्न स्थानों तक आने-जाने के लिए सुविधाजनक, किफायती और त्वरित स्थानीय परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बाइक रेंटल सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें बिलासपुर में कम दूरी के लिए तुरंत आने जाने की जरूरत होती है। इसके माध्यम से यात्री टैक्सी या ऑटो के लिए इंतजार किए बिना अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा कर सकेंगे। इससे न केवल यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी।

जंगल में गाय से चमड़ी निकालते 6 गिरफ्तार

कोंडागांव। ज़िले के इरागांव थाना क्षेत्र में गौ हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। जंगल में गौ को काटकर उसकी चमड़ी निकालते हुए मौके से पकड़े गए आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि शोक कार्यक्रम के लिए मांस तैयार करने के उद्देश्य से गौहत्या की गई थी। घटना की सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली थी। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी इरागांव पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ग्राम पहुँचे के जंगल क्षेत्र में पहुँची, जहाँ छह लोग कथित रूप से गाय को काटकर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे। पुलिस ने सभी को मौके से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी अरुण कुमार नेताम ने बताया कि गौहत्या की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने जंगल में दृबिश दी थी। मौके पर छह लोगों को पकड़ा गया, जो एक शोक कार्यक्रम के लिए गौ की हत्या कर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे। पुलिस ने घटना स्थल से आरोपियों को गिरफ्तार

162 एकड़ फसल पर मंडरा रहा खतरा बांध की मरम्मत

कवर्धा। कबीरधाम जिले के बेलहारी बांध के तटबंध की मरम्मत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से मरम्मत कार्य पूरा होने के महज तीन महीने बाद ही पहली बारिश में तटबंध की मिट्टी बहने लगी है। जगह-जगह पानी का रिसाव होने से ग्रामीणों में बांध के कमजोर होने और टूटने का डर बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के दौरान तटबंध में मिट्टी डालने के बाद उसका पर्याप्त कंपैक्शन नहीं किया गया। यही वजह है कि बारिश और पानी के दबाव के चलते मिट्टी बहने लगी और तटबंध कमजोर हो गया। स्थिति को देखते हुए बांध का पानी नहर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। बेलहारी बांध के तटबंध की मौजूदा स्थिति ने आसपास के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के मुताबिक यदि तटबंध टूटता है तो करीब 162 एकड़ खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों को आशंका है कि पानी का दबाव बढ़ने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है।

चिरायु टीम की पहल से तीन बच्चों को मिला नया जीवन

धमतरी । राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच, बीमारियों की शीघ्र पहचान और उन्हें समय पर उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों ने तीन परिवारों के जीवन में नई उम्रीद जगाई है। चिरायु टीम-बी मगरलोड की सतर्कता और तत्परता से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित तीन बच्चों की समय रहते पहचान हुई और उन्हें विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया गया। विगत 4 अगस्त को चिरायु टीम-बी मगरलोड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान केरिना कंवर (15 वर्ष), कुमकुम साहू (3 वर्ष) एवं युशेश कुमार (9 वर्ष) में संभावित जन्मजात हृदय रोग के लक्षण पाए गए। टीम ने बिना विलंब किए बच्चों को आवश्यक जांच एवं विशेषज्ञ उपचार के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल, रेफर किया



तथा उपचार प्रक्रिया में आवश्यक समन्वय और फॉलोअप सुनिश्चित किया। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय जांच एवं परीक्षण किए गए। जांच में जन्मजात हृदय संबंधी समस्या की पुष्टि होने के बाद तीनों बच्चों को सर्जिकल उपचार की आवश्यकता बताई गई। चिकित्सकों की देखरेख में तीनों बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया। उपचार के पश्चात बच्चों के स्वास्थ्य में संतोषजनक

सुधार हुआ और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया। चिरायु टीम द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेते हुए उपचार के बाद भी आवश्यक फॉलोअप किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में चिरायु टीम की भूमिका केवल बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों को उचित स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने, उपचार के लिए समन्वय स्थापित करने और उपचार के बाद स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करने

तक रही। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कितनी महत्वपूर्ण है।जन्मजात हृदय रोग कई बार बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान संभावित लक्षणों की पहचान बच्चों को गंभीर जटिलताओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिरायु कार्यक्रम इसी उद्देश्य से बच्चों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर उन्हें आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है।तीनों बच्चों का सफल उपचार उनके परिवारों के लिए राहत और खुशी का विषय है। यह सफलता समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, प्रारंभिक पहचान, त्वरित रेफरल, विशेषज्ञ उपचार और सतत फॉलोअप के प्रभावी समन्वय का उदाहरण है।

आदि सेवा केंद्रों में 15 अगस्त तक जनसुनवाई

महासमुंद्र। जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं और विभिन्न सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी सेवा केंद्रों में 13 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक तीन दिवसीय जनसुनवाई एवं सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का आयोजन प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसी क्रम में आज जिले के आदि सेवा केन्द्रों में आयोजित शिविर में आदिवासी कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, लोक

स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग सहित बैंक, सीएससी एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा सेवाएं एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। तीन दिवसीय शिविर में ग्रामीणों की शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं शिकायतों का निराकरण करने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी एवं जागरूकता भी प्रदान की किया जाएगा। सीएससी एवं सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं और आवेदनों में नागरिकों की

सहायता की जाएगी। बैंकिंग सेवाओं एवं बैंक खातों से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन भी उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, एनसीडी स्क्रीनिंग, पोषण संबंधी जागरूकता, आवश्यकता अनुसार एनआरसी रेफरल सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा। राजस्व संबंधी सेवाओं में जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र, एग्रीस्टेक से संबंधित कार्य तथा अन्य आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा उल्लस, माय भारत और नेशनल कैरियर सर्विस सहित विभिन्न ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी शिविर में उपलब्ध रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय काफेर में राजस्व मंत्री टंकराम करेंगे ध्वजारोहण

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा कांकेर जिला मुख्यालय के नरहरदेव हाइयर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। मंत्री श्री वर्मा परेड की सलामी लेंगे और जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गरिमामय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होगा। कार्यक्रम में हर्ष फायर और मार्च पास्ट के बाद शालेय छात्र-छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति तथा पुरस्कार वितरण किया जायेगा।

स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय कवर्धा में उद्योग मंत्री देवांगन करेंगे ध्वजारोहण

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर कबीरधाम जिले के प्रभारी एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जिला मुख्यालय कवर्धा के आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर करेंगे। जिले के प्रभारी एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन परेड की सलामी लेंगे और जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गरिमामय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होगा। कार्यक्रम में हर्ष फायर और मार्च पास्ट के बाद शालेय छात्र-छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। समारोह में पुरस्कार वितरण के बाद मुख्य अतिथि प्रस्थान करेंगे।

मनेन्द्रगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी, मंत्री जायसवाल करेंगे ध्वजारोहण

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्री श्री रयाम बिहारी जायसवाल इस वर्ष मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी आमंत्रण पत्र के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2026 को प्रातः 9:00 बजे पुलिस ग्राउंड आमाखेरवा, मनेन्द्रगढ़ में गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न होगा। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम की समय-सारणी इस प्रकार है- प्रातः 08:58 बजे माननीय मुख्य अतिथि का आगमन, प्रातः 09:00 बजे राष्ट्रगीत, ध्वजारोहण, सलामी एवं राष्ट्रगान, प्रातः 09:07 बजे मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण, प्रातः 09:15 बजे मार्च पास्ट, प्रातः 09:25 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन, प्रातः 09:45 बजे स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रातः 11:00 बजे उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण, प्रातः 11:15 बजे भव्य कार्यक्रम का समापन होगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी मस्जिद, दरगाह, मदरसा में तिरंगा फहराया जाये

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा यौमे आजादी (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को राज्यभर की सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की गई है एवं कहा गया है कि, इस सम्बंध में कार्यालय छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पूर्व में जो दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं वह यथावत् रहेंगे, जिसका पालन सभी वक्फ संस्थाओं के पदाधिकारीयों को किया जाना है। यौमे आजादी (स्वतंत्रता दिवस) के महत्व को समझते हुए इस पर्व के देशभक्ति, आपसी एकता और भावचारे के साथ मनएं। हमारा देश सुफ़ी-संतों का देश है यहां हर जाति, धर्म, पंथ, समाज के लोग गंगा-जमुना तहजीब के साथ मिल-जुल कर रहते हैं। इस्लाम धर्म, मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है इसलिए मुल्क की आजादी के इस पर्व पर देश के प्रति अपना प्रेम और संविधान के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए ध्वजारोहण करना चाहिए। जो लोग ध्वजारोहण के खिलाफ है वो देशभक्त नहीं है बल्कि देशद्रोही है ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए जिन्हें तिरंगा फहराने से तकलीफ होती है।

अहिल्याबाई होल्कर की पुण्यतिथि पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया पुण्य स्मरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने नारी शक्ति की सशक्त प्रतीक एवं महान लोकसेविका लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर का जीवन नारी शक्ति, साहस, नेतृत्व और सेवा भावना का प्रेरणादायी उदाहरण है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने अपने कुशल प्रशासन, न्यायप्रियता, जनसेवा और धर्म-संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से देश के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने शासनकाल में जनकल्याण की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाज के सभी वर्गों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए।

राजधानी/छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के स्टील का प्रदेश में ही हो अधिकतम मूल्य संवर्धन : मुख्यमंत्री

डाउनस्ट्रीम और स्पेशियलिटी उत्पादों के निर्माण पर दें जोर, ग्रीन स्टील पर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग में 13,840 करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ में 13,840 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में 10,921 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्टील और खनन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान की मजबूत नींव हैं और आगे भी हमारी ताकत बने रहेंगे। अब समय इस मजबूत नींव पर औद्योगिक विकास की नई इमारत खड़ी करने का है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्टील उत्पादन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्टील का अधिकतम मूल्य संवर्धन भी प्रदेश के भीतर ही होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्टील प्राथमिक रूप में प्रदेश से बाहर जाने के बजाय यहीं आंटो कम्पोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे, रक्षा और सौर



ऊर्जा उपकरणों जैसे डाउनस्ट्रीम एवं स्पेशियलिटी उत्पादों में परिवर्तित हो। जब मूल्य संवर्धन छत्तीसगढ़ में होगा, तो रोजगार भी छत्तीसगढ़ में ही सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप दुनिया तेजी से ग्रीन स्टील की ओर बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों

में है, जिन्होंने इस बदलाव को समय रहते अपनाया है। प्रदेश में 26 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत उपलब्धता तथा प्रतियस्पर्धी औद्योगिक विद्युत दरें ऊर्जा-आधारित डाउनस्ट्रीम मैनुफैक्चरिंग के लिए छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से अनुकूल बनाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने निवेश के नए द्वार खोले हैं। पिछले 18 महीनों में प्रदेश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टील और खनन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी बड़े निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कारोबारी प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किए हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने ‘ईज ऑफ डूइंग

बिजनेस एक्ट’ लागू किया है। इसके तहत कम जोखिम वाले उद्यमों के लिए स्व-प्रमाणीकरण, जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था तथा निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं होने पर डीम्ड अफ़क्वल जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सुधारों से प्रदेश के लगभग 15 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है। CRISIL-NITI Aayog Investment Friendliness Index 2026 में छत्तीसगढ़ ने प्रमुख राज्यों के बीच ‘रेगुलेटरी ईज’ और ‘इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट’ में प्रथम स्थान तथा ‘एनवायरनमेंटल रेंजिलिएंस’ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के दसवें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को GeM Sustainable Procurement Award से भी सम्मानित किया गया है।

राज्य सरकार औद्योगिक विकास को रायपुर-भिलाई के परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र से आगे प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दे रही है। राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा और बस्तर जिलों में चार नए औद्योगिक

पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने राजनांदगांव में लगभग 306 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश और लगभग 9 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कंपनियों ने इस क्लस्टर में रुचि दिखाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, हमारी नीति स्पष्ट है, प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और अनुमतियां तय समय-सीमा में मिल रही हैं। यहां रेड टेप के लिए कोई जगह नहीं है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और साथ मिलकर सफलता की नई कहानी लिखेंगे।उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउनस्ट्रीम मैनुफैक्चरिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ अब अपनी खनिज संपदा को प्रदेश के भीतर ही अधिक मूल्य, अधिक निवेश और अधिक रोजगार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सीएम साय रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण, सुरक्षा बलों की टुकड़ियां परेड रिहर्सल में

रायपुर। आजादी का जश्न बड़े धूमधाम से हर साल की तरह इस साल भी राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा। आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस में 16 प्लाटून शामिल हैं। जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल के साथ ही डॉग शो और हॉर्स शो के साथ ही स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त के दिन सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम भी पुलिस के द्वारा किए गए हैं।

परेड प्रभारी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारी 29 जुलाई से की जा रही है। जिसका अंतिम रिवर्सल 13 अगस्त को होगा। राज्य स्तरीय परेड होने की वजह से स्वतंत्रता



दिवस में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे।

सूरज सिंह परिहार ने बताया आयोजन की भव्य तैयारी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य परेड समारोह में इस बार 16 प्लाटून शामिल होंगे। जिसमें जिसमें सेंट्रल फोर्सज की टुकड़ियां, जिला बल टुकड़ियां होंगे। इन 16 प्लाटून में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टुकड़ी भी है जबकि एक टुकड़ी बिहार से भी आई हुई है।

सें्ट्रल फोर्सज की टुकड़ी में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसफ की टुकड़ी भी इस प्लाटून में शामिल है। जेल और नगर सेना की टुकड़ी के साथ ही एनसीसी भी शामिल है। स्वान दल और अश्वारोही दल भी शामिल है। मुख्य परेड के आयोजन के बारे में उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का अभिभाषण के बाद मेडल सेरिमनी डॉग शो और हॉर्स शो के साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा।

सेंट्रल फोर्सज की टुकड़ी में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसफ की टुकड़ी भी इस प्लाटून में शामिल है। जेल और नगर सेना की टुकड़ी के साथ ही एनसीसी भी शामिल है। स्वान दल और अश्वारोही दल भी शामिल है। मुख्य परेड के आयोजन के बारे में उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का अभिभाषण के बाद मेडल सेरिमनी डॉग शो और हॉर्स शो के साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने तिरंगा

मंत्री राजवाड़े की अगुवाई में दो किमी तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस यात्रा में लगभग एक हजार लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

तिरंगा यात्रा शासकीय कन्या हाई स्कूल, विश्रामपुर से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक तक पहुंची और निर्धारित मार्ग से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। करीब दो किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा थामे स्कूली छात्र-छात्राएं, नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी-कर्मचारी देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष से पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। विद्यार्थियों और नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता ने आयोजन को विशेष उत्साह और गरिमा प्रदान की।



मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की आन-बान-शान का प्रतीक है और हर नागरिक का दायित्व है कि वह तिरंगे के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाए। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और जनभागीदारी का व्यापक जनआंदोलन है।

तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और तिरंगे के सम्मान का संदेश प्रभावी रूप से प्रसारित किया गया। आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

ननकीराम कंवर ने फिर लिखा पीएम मोदी को पत्र

रायपुर। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर ने एक बार चर्चा में हैं। अबकी बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वस्तु एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी) में वर्ष 2021 और 2022 में हुई पदोन्नति परीक्षाएं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।

ननकीराम कंवर ने पत्र में बताया कि राज्य कर निरीक्षक के 42 पदों के लिए दो सालों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 350 कर्मचारियों ने भाग लिया। लेकिन इस परीक्षा में विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर व्यापम से सहयोग न लेते हुए खुद परीक्षा आयोजित की और गड़बड़ियां की।

कंवर ने आरोप लगाया कि जो कर्मचारी पास हुए, उनके अंक 80 से 100 प्रतिशत तक हैं. यह



इशारा करते हैं कि उन्हें पहले से ही प्रश्न पत्र मिल चुके थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में विभागीय आयुक्त समीर बिश्नोई के पीए और अन्य अफसरों से जुड़े लोगों को चयनित किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं पर न तो कोई मोहर लगी थी, न किसी अधिकारी के हस्ताक्षर, जिससे आसानी से उत्तर बदले जा सकते थे।

कंवर ने कहा कि तत्कालीन आयुक्त समीर बिश्नोई वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में जेल में हैं। इससे यह तय है कि परीक्षा भी भ्रष्ट तरीके से कराई गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए और यदि गड़बड़ी साबित हो, तो भर्ती को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाए।

कांग्रेस की गुटबाजी और नेतृत्वहीनता से चरमराया संगठनात्मक ढाँचा: भाजपा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर गहराती अंतकलह, गुटबाजी और संगठनात्मक बिखराव पर तीखी टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के

प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से नेतृत्वहीनता और आंतरिक कलह के दौर से गुजर रही है, जहाँ जनसेवा की जगह केवल कुर्सी की लड़ाई और गुटीय वर्चस्व की होड़ मची हुई है। दीपक ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस संगठन और युवा नेताओं के बीच आंतरिक खींचतान व गुटबाजी लुप्तकर सामने आ गई है। युकां प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक नाम पर आम सहमति बनाने का प्रयास पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। वरिष्ठ नेताओं में सहमति बनने से पहले ही विभिन्न गुटों में शह-मात का खेल शुरू हो गया। उज्ज्वल दीपक ने कहा कि एक तरफ जहाँ प्रदेश अध्यक्ष पद के



बहुकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया और नियमों को लेकर युवा नेताओं में भारी नाराजगी व्याप्त है।

कई प्रमुख युवा नेता चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराने और आलाकमान के समक्ष अपनी बात रखने दिखी पहुँच चुके हैं। ?वरिष्ठ नेताओं की चेतावनी के बावजूद यदि यह चुनावी रार शांत नहीं हुई, तो युवक कांग्रेस का यह चुनाव संगठन के भीतर जारी गुटीय राजनीति का नया अखाड़ा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि चाहे युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में चल रहे अंदरूनी घमासान और धांधली के आरोप हों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही आपसी खींचतान हो, या फिर ईडी की वैधानिक कार्रवाइयों के खिलाफ आयोजित निष्प्रभ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस का आपसी विवाद अब बंद कमरों से निकलकर पूरी तरह सड़कों पर आ चुका है।

दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवायें पहुंचायें: मुख्य सचिव

■ नविकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न

रायपुर। मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 102वें एवं 103वें संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मार्च 2026 और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी हितग्राही योजनाओं में वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का बिना किसी बाधा के त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि ऋण



प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए।

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शीघ्रता से लोन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए भी कीसीसी वितरण की समीक्षा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए बेहद कम ब्याज (मात्र 4%) पर आसान लोन देती है। बिना किसी गारंटी के मिलने वाले इस लोन की सीमा को

बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है, जबकि कुल ऋण सीमा को 5 लाख तक किया गया है।

राज्य के बस्तर और खरगुना संभागों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए, वहां नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वित्तीय सेवा विभाग के मानकों के अनुसार, बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग सेवाएं (शाखाएं या बीसी एजेंट) उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की गतिविधियों, जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े विषयों के समीक्षा की गई। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के प्रतिनिधियों सहित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

संसदीय समिति की रिपोर्ट से उठते सवाल

संतोष कुमार पाटक

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में प्राइवेट यानी निजी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई है। देश के राज्य और जिले तो छोड़िए , अब तो छोटे-छोटे शहरों में भी खुलते जा रहे नर्सिंग होम और स्कूल लोगों की जेब काटने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। देश का गरीब तबका तो छोड़िए, मध्यम आय और उच्च मध्यम आय की कैटेगरी में आने वाले लोग भी इनकी लूट से परेशान होते जा रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों को लेकर आई संसदीय समिति की एक रिपोर्ट ने फिर से इस धाव को ताजा कर दिया है। एक बार फिर से वही पुराना सवाल उठ कर खड़ा हो गया है कि खुली लूट का अड्डा बन चुके प्राइवेट अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी पर आखिर कब लगाम लगेगी ? देश के प्राइवेट अस्पताल, भर्ती होने वाले मरीजों/ उनके परिजनों से कमरे का जो किराया वसूलते है, यह उसी इलाके के महंगे होटलों से भी कई गुना ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, इलाज के नाम पर जो बाकी चार्ज लिए जाते हैं वो कमरे के चार्ज में अलग से जोड़ा जाता है। यह सारे खुलासे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से हुए हैं। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में इलाज का खर्च औसतन 6,631 रुपए है जबकि प्राइवेट अस्पतालों में यही खर्च साढ़े सात गुने से भी ज्यादा (50,508 रुपए) है। इलाज के नाम पर भी अनाप-शनाप वसूली की जाती है। बिल में पारदर्शिता नहीं होती है, गंभीर इलाज या सर्जरी से पहले मरीज को फाइनल खर्च का एस्टिमेंट नहीं बताया जाता है। नतीजा प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बेलगाम होती जा रही है और जिसकी जो मर्जी वो वसूल रहा है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में कमरे का चार्ज 6 से 12 हजार रुपए प्रतिदिन है जबकि उसी इलाके के 3 स्टार होटल में कमरे कमरे का चार्ज 2500 से लेकर 4500 रुपए के बीच ही है। दिल्ली के साकेत में स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीज से अस्पताल वाले 7-11 हजार रुपए प्रतिदिन कमरे का चार्ज वसूलते है जबकि अस्पताल के पास ही स्थित होटल में आपको 2100 से 3500 रुपए प्रतिदिन के आधार पर बढ़िया कमरा मिल सकता है। यही हाल देश के ज्यादातर शहरों में प्राइवेट अस्पतालों का है। समिति ने सरकार को कुछ सुझाव देते हुए यह सिफारिश की है कि, प्राइवेट अस्पताल के कमरे का किराया 3 स्टार होटल के किराए से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती से पहले अस्पताल को इलाज का पूरा खर्च स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। सर्जरी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए फिक्स रेट तय होना चाहिए और उसमें सभी खर्च शामिल होने चाहिए। इसके अलावा भी संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिश करते हुए सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। समिति ने स्पष्ट तौर पर सरकार को सरकारी अस्पतालों में बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने को कहा है। हालांकि यह सब जानते हैं कि सरकार ऐसा करेगी नहीं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय समिति की रिपोर्ट की आड़ लेकर कहीं वैसा ही खेल न कर दें जैसा कि सीजीएचएस चार्ज के मामले में किया गया है। सरकार को यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि दिल्ली या मुंबई के महंगे अस्पतालों में इलाज का खर्च इन शहरों के हिसाब से है वहीं देश के दूर-दराज इलाकों में इलाज का खर्च उस इलाके के आधार पर है। डर इस बात का है कि कहीं सीजीएचएस में जो गलतियां की गई है,उसी तरह की गलती को इस मामले में दोहराते हुए दिल्ली या मुंबई के आधार पर इलाज् और सर्जरी का फिक्स रेट पूरे देश के लिए न तय कर दिया जाए।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)
खगोल की विस्तृत सीमा
जिस प्रकार पूर्वोंक वर्णन के अनुसार ब्रह्माण्ड के एक कपाल भू-मण्डल की सीमा पचास करोड़ योजन तक विस्तृत सिद्ध की जा चुकी है। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के दूसरे कपाल खगोल का परिमाण भी पूरा पचास करोड़ योजन बताया गया है। यथा-
एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति।
यथा हि द्विदलयोनिष्पावादीनाम् ।।

(श्रीमद्भागवत 5 । 12। 12)
अर्थात्- भूमण्डल के परिमाण के अनुसार ही युमण्डल (खगोल) का परिमाण भी खगोलवेत्ता महर्षियों ने बतलाया है, जैसे कि दो दलों वाले मटर आदि अन्न के एक दल का परिमाण प्रकट कर देने पर दूसरे दल का परिमाण भी तत्सम ही होता है (इसीप्रकार अण्डकार ब्रह्माण्ड के पृथ्वी-सम्बद्ध गोलाधं को भू-मण्डल और तारागण सम्बद्ध गोलाधं



को ह्यूमण्डल कहते हैं- इन दोनों का परिमाण समान ही है)।

शनि गुरु और मंगल की विशेषता
आधुनिक खगोलवेत्ताओं ने जाना है कि शनि ग्रह सब ग्रहों से गति में सुस्त है, परन्तु पुराण-ग्रन्थों में इसका नाम ही पंगु या शनैश्चर लिखा है, जिसका अर्थ लंगड़ा या धीरे धीरे चलने वाला होता है। वे बृहस्पति ग्रह को सूर्य के अतिरिक्त सब ग्रहों से बड़ा बताते हैं तो पुराण पूर्व ही से इसे गुरु और बृहस्पति अर्थात् भारी और बड़ा कहते हैं। इसी प्रकार आजकल मङ्गल के विषय में जो खोज हो रही है उसका सारांश यही है कि मङ्गल निवासी जीव हम पृथ्वी-निवासियों से बहुत कुछ समता रखते हैं अर्थात् उनके शरीर वैसे ही तत्त्वों के विमिश्रण से बने हैं जैसे तत्त्वों से हम भूमि-निवासियों के, परन्तु पुराण ग्रन्थों में इसे स्पष्टतया भीम या भूमिपुत्र कह कर हमारा पृथ्वी का बेटा सिद्ध किया गया है।

क्रमशः ...

27 नाम, एक संदेश: अरुणाचल प्रदेश पर भारत नहीं झुकेगा

अरुणिम भूयान

अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के आधिकारिक नाम रखने का भारत का फैसला और उसका समय, दोनों ही बहुत अहम हैं। यह घोषणा पिछले ससाह भारत-चीन सीमा मामलों पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 36वीं बैठक के एक दिन बाद की गई। इससे पता चलता है कि विवादित सीमा के प्रबंधन पर बातचीत के साथ-साथ अपने इलाके पर दावे को मजबूती से बनाए रखने का काम भी चल रहा है – जो भारत-चीन के बीच रिशतों में आई मौजूदा नरमी को सीमाओं को भी दिखाता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने निर्गमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने यह बात अरुणाचल प्रदेश में इन जगहों के नाम रखने पर चीन की आलोचना के जवाब में कही। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा तथ्य है जो स्वतः स्पष्ट है। साथ ही, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकती। सात अगस्त को गृह मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सलाह-मशविरे के बाद, उसने सभी ऑफ ईंडिया के आधिकारिक नक्शों पर मानक नामों के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 27 जगहों और विशेषताओं की पहचान की है। मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के सर्वे ऑफ ईंडिया के नक्शे पर औपचारिक रूप से इनकी पहचान करने का उद्देश्य इनकी उन्हीं पहचान को आसान बनाना और आम जनता के बीच इनके बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करना है।

सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैली बस्तियां, इलाकों, पहाड़ी दर्रों, एक झील और एक सैन्य स्मारक समेत 27 जगहों की पहचान की है। इन बस्तियों और इलाकों में लोंगजू, माजा, बिषा, बड़ा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, टेरि्टनगर, रामनगर, जसवंत



गढ़, सागर, पद्या, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलांग नगर शामिल हैं। भौगोलिक विशेषताओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे – जो ला, रिजा ला, पुकुर ला और थांग ला – शामिल हैं। इस सूची में शंभो सरोवर (एक झील) और शेर-ए-थापा स्मारक भी शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में भारत के सैन्य इतिहास और मौजूदगी की याद दिलाते हैं। चीन ने सोमवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल प्रदेश (जिसे बीजिंग जांगनान या दक्षिणी तिब्बत कहता है) में जगहों के नाम रखने के भारत के कदम को बेअसर और अमान्य करार दिया। बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, जांगनान क्षेत्र चीन का इलाका है। चीन भारत द्वारा अवैध रूप से बनाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। चीन द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे नामों को अपने तथाकथित मानक नामों से बदलने की भारत की कोशिश गैर-कानूनी, बेअसर और अमान्य है। इससे यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि जांगाना क्षेत्र चीन का है।

भारत का यह कदम डब्ल्यूएमसीसी की बैठक के ठीक एक दिन बाद उठाया गया, जो भारत-चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति के बारे में एक अहम जानकारी देता है: नई दिल्ली बीजिंग के साथ अपने संबंधों को स्थिर और प्रबंधित करने की इच्छुक है, लेकिन अपने मुख्य क्षेत्रीय हितों से समझौता करने

ज्ञान/मीमांसा

संसद में आखिर कब होगी मुद्दों पर चर्चा?

कतिलाल मांडेठ

संसद का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ देश की जनता ने जनप्रतिनिधियों को संसद भेजा था, वह उम्मीद लगातार कमजोर होती जा रही है। मंगलवार को एक बार फिर संसद परिसर से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। संसद के बाहर एनडीए सांसदों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तो विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए। दोनों पक्षों के सांसद आमने-सामने आए और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। परिणाम यह हुआ कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही समय बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त को समाप्त हो चुका हैं। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां देश के करोड़ों लोगों से जुड़े मुद्दों पर बहस, सवाल और समाधान की उम्मीद की जाती है। लेकिन लगातार हंगामे और नारेबाजी के कारण सांसदों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है।

मंगलवार को संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने मकर द्वार तक विरोध मार्च निकाला। उनके हाथों में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर थे और वे झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे थे। भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वहां पहुंचीं। भाजपा सांसदों की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। प्रियंका गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल भी चुके हैं।

यह घटनाक्रम संसद के भीतर चल रहे राजनीतिक टकराव का विस्तार ही नजर आया। विपक्ष झारखंड में छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि गृह



मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष केवल गृह मंत्री की राय सुनना नहीं चाहता, बल्कि यह जानना चाहता है कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी का आदेश किसने दिया।

कांग्रेस की ओर से भी सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना के तुरंत बाद उसकी निंदा की थी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं हैं और विपक्ष सरकार का जवाब सुनने के बजाय केवल आरोप लगाना चाहता है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी राहुल गांधी पर सदन चलने देने से बचने का आरोप लगाया और कहा कि जब गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं तो विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए।

राजनीतिक दलों के बीच इस आरोप-प्रत्यारोप का सबसे बड़ा नुकसान संसद के कामकाज को हो रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने से बच रही है। लोकतंत्र में दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन संसद का उद्देश्य केवल एक-दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाना नहीं है। सत्ता पक्ष के पास सरकार चलाने की जिम्मेदारी है तो विपक्ष के पास सरकार से सवाल पूछने और उसकी नीतियों की जांच करने की जिम्मेदारी है। दोनों भूमिकाएं लोकतंत्र के लिए समान रूप से जरूरी हैं।

विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने, विरोध दर्ज कराने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का पूरा अधिकार है। इसी तरह सरकार को भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने और अपनी

नीतियों का पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करने का माध्यम बन जाता है, तब लोकतांत्रिक बहस कमजोर पड़ती है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किस दल ने ज्यादा नारे लगाए या किसने किसके खिलाफ पोस्टर दिखाए। असली सवाल यह होना चाहिए कि देश की जनता के लिए संसद ने क्या काम किया।

संसद में एक दिन की कार्यवाही पर सार्वजनिक धन का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। सांसदों के वेतन और भत्तों से लेकर संसद की सुरक्षा, प्रशासन, कर्मचारियों और अन्य व्यवस्थाओं तक जनता के कर से प्राप्त धन खर्च होता है। इसलिए संसद का प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण है। जब सदन लगातार स्थगित होता है तो नुकसान केवल सरकार या विपक्ष का नहीं होता, बल्कि सीधे जनता का होता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से चुनकर आए सांसद अपने क्षेत्रों की समस्याएं संसद में उठाने का अवसर खो देते हैं।

देश में इस समय रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, युवाओं के भविष्य, बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था जैसे अनेक मुद्दे हैं। अलग-अलग राज्यों के सांसद अपने क्षेत्र की सड़क, पानी, बिजली, रेल, उद्योग, सिंचाई और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को संसद के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक टकराव के कारण उनका समय हंगामे में निकल जाता है। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है।

यह भी सही है कि केवल विपक्ष को संसद ठप होने के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष द्वारा उठाए गए गंभीर मुद्दों को पर्याप्त महत्व दे और संवाद का रास्ता खुला रखे। विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार के जवाब को सुने और असहमति होने पर संसदीय तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराए। संसद में बहस हो, तीखी बहस हो, सरकार की आलोचना हो, लेकिन चर्चा का मंच बंद नहीं होना चाहिए।

संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं है। लोकतांत्रिक राजनीति में विरोध प्रदर्शन और असहमति स्वाभाविक हैं। कई बार विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सदन में विरोध का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब

विभाजन विभीषिका दिवस



आधुनिक काल में मनुष्यता पर विभाजन द्वारा बड़ा संकट खड़ा किया। सन् 1905 में बंगाल के धर्म आधारित विभाजन के बाद से ही विभाजन की कुत्सित रूपरेखा बनना शुरू हो गई थी, विभिन्न इतिहासकारों ने अंग्रेजों के इस कदम को भारत विभाजन के बीज के रूप में देखा है। वहीं विभाजन के जिम्मेदारों पर बात करते हुए समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मेन ऑफ़ पार्टिशन में लिखा है कि कई बड़े कांग्रेसी नेता जिनमें नेहरू भी शामिल थे वे सत्ता के भूखे थे जिनकी वजह

से बँटवारा हुआ। विभाजन की विभीषिका ने जिन लोगों को असमय मृत्यु की ओर ढकेल दिया, जिन परिवारों के साथ अमानवीय ज्यादतियाँ हुई –क्या देश को वर्तमान आधुनिक लोकतांत्रिक देश बनाने तथा स्वतंत्रता दिलाने में उनका योगदान था ? यदि हाँ, तो उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा करते हुए यह कहा देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। आज़ादी

के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ़ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को ख़त्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होगी। देश जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है तो विभाजन के कारण अपने प्राण खोने वाले नागरिकों को ससम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करना, निश्चित ही स्वागत योग्य है। देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से विभाजन की मानवीय त्रासदी को पुनः रेखांकित किया जा रहा है, इस पुनः रेखांकित को देश के बाहर और बहुत ही सीमित संख्या में देश के अंदर गैर-जरूरी माना जा रहा है।

आज का इतिहास

1862 बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना ।
1908 इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित।
1917 चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1920 बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई।
1936 बर्लिन में पहला ओलम्पिक बास्केटबॉल खेल हुआ।
1938 बीबीसी की पहली फीचर फ़िल्म (स्टूडेंट ऑफ़ प्राम्ट) टेलीविजन पर प्रसारित हुई।
1947 भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक् राष्ट्र बना।
1968 मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान–ए–पाकिस्तान से सम्मानित किए गए।
1971 बहरीन को 110 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली।
1975 पाकिस्तानी सेना ने राष्ट्रपति मुजीब उर–रहमान का तख्तापलट किया।
1996 प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबन्धकार, समीक्षक तथा अनुवादक अमृतराय का निधन 14 अगस्त 1996 को हुआ।
2000 भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक़्केबाज हवा सिंह का निधन 14 अगस्त 2000 को हुआ।
2001 मेसेडोनिया सरकार व अल्बानियाई विद्रोहियों में समझौता, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी द्वारा निशस्त्रीकरण से इन्कार।
2002 पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ़ ने कश्मीर के चुनावों को ढोंग करार दिया।
2006 संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इस्लामेल और दक्षिणी लेबनान में पांच सप्ताह से जारी संघर्ष थमा।
2006 इराक के कहतानिया में बमबारी में 400 लोग मारे गये।
2007 पाकिस्तानी राष्ट्रध्यक्ष परवेज मुशर्रफ़ तथा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर के मध्य समझौता हुआ।
2010 भारत सरकार ने 14 अगस्त 2010 में 64वें स्वतंत्रता दिवस पर काबुल में शहीद हुए सेना न्कित्सा कोर्ने के मेजर एल ज्योतिन सिंह को अशोक चक्र तथा विनोद चौबे और मेजर दिवेंद्र सिंह जस को कीर्ति चक्रप्रदान करने की घोषणा की।
2011 प्रसिद्ध हिन्दी फ़िल्म अभिनेता शम्मी कपूर का निधन 2011 को हुआ।
2012 महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का निधन 14 अगस्त 2012 को हुआ।
2013 मिश्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 638 लोग मारे गये।
2017 प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का निधन 14 अगस्त 2017 को हुआ।

आकाश आनंद के नये नारे ने उड़ा दी यूपी में सारे राजनीतिक दलों की नींद

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो लोग बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को हल्के में लेकर चल रहे थे, उन्हें अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं और उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़, खासकर युवाओं की मौजूदगी, पार्टी के लिए नई उम्मीद पैदा कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आकाश आनंद ने बसपा की रैलियों में बड़ी भीड़ आकर्षित की थी, हालांकि इसका चुनावी परिणाम पार्टी के लिए शून्य रहा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं और इसी अंतर को समझते हुए आकाश आनंद इस बार बसपा के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं।

पिछले दिनों बसपा के भीतर हुई राजनीतिक उठापटक और संगठनात्मक चुनौतियों के बीच आकाश आनंद का यह आक्रामक अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा महज एक सीट पर सिमट गई थी। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव बसपा और खुद

आकाश आनंद के लिए राजनीतिक अस्तित्व तथा प्रभाव की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

हम आपको बता दें कि सोमवार को हाथरस के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी अविन शर्मा के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों सम्मेलन में आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर रोजगार, शिक्षा और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से पिछले दस वर्षों के कामकाज का हिसाब मांगा जाना चाहिए। आनंद का आरोप था कि सरकार ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए पिछले एक दशक में विज्ञापनों पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए।

युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में चार लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उनका कहना था कि यदि विज्ञापन पर खर्च होने वाली रकम का इस्तेमाल परीक्षाओं और रोजगार के लिए किया जाता तो बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल सकती थीं। आनंद ने रोजगार के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप



लगाया कि सप्ताह में एक दिन नाश्ता बेचने या सड़क किनारे ठेला लगाने वाले व्यक्ति को भी रोजगार के आंकड़ों में शामिल कर दिया जाता है। अखबार

शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए आनंद ने दावा किया कि प्रदेश में 25 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। उन्होंने झांसी मंडिकल कॉलेज में शिशुओं की मौत का भी जिक्र किया और सरकार से शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पर जवाब मांगा। विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया

विदेश में छिपना अब नामुमकिन: भगोड़ों की स्वदेश वापसी का बना नया रिकॉर्ड

विवेक शुक्ला

भारत में अपराध करके विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों और अन्य गंभीर अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। 2018 में पेश ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल’ इस दिशा में निर्णायक मोड़ लाया। तब से लेकर आज तक भारत ने विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। पिछले छह वर्षों में 274 भगोड़ों को विभिन्न देशों से भारत लाया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 2025 में अकेले 70 और जुलाई 2026 तक 45 भगोड़ों की वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है।

ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अपराधियों को विदेश में शरण देकर देश के कानून से बचने की प्रवृत्ति को तोड़ना अब राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है।

भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सक्रिय, तेज और प्रभावी बनाने का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। विदेशों में छिपे भगोड़ों को वापस लाने में गृह मंत्रालय मुख्य समन्वयक और नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। हर भगोड़े के कानूनी दस्तावेज (डोजियर) तैयार करवाना, विदेशी समकक्षों के साथ दस्तावेजों का आदान-प्रदान और औपचारिक अनुरोध से पहले सबूतों का आकलन-सत्यापन – ये सभी जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय के पास हैं।

प्रत्यर्पण की सफलता इन्हीं मजबूत सबूतों और दस्तावेजों पर निर्भर करती है। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल के वैश्विक नेटवर्क के साथ मिलकर अलर्ट और ट्रैकिंग को तेज करने के लिए ‘भारतपोल’ प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सीबीआई द्वारा विकसित यह डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरपोल से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाता है, जिससे देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से सहयोग और समन्वय कर सकती हैं।



वर्तमान में भारतपोल प्लेटफॉर्म से राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन की 1,400 से अधिक इकाइयां जुड़ी हुई हैं। इससे अपराधियों की ट्रैकिंग वास्तविक समय में संभव हो गई है। अब 3 से 20 दिन के अंदर क्रिमिनल्स की गतिविधियां प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं और प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गृह मंत्रालय रेड कॉर्नर नोटिस के जरिये विश्व भर में अलर्ट भेज रहा है।

अकेले 2026 में 182 भगोड़ों के बारे में नोटिस जारी किए गए। जनवरी 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के मल्टी-एजेंसी सेंटर और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का गठन कर हार्ड-प्रोफाइल भगोड़ों पर नजर रखने और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने का काम तेज कर दिया गया।

पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने 137 प्रत्यर्पण अनुरोध विदेशी सरकारों को भेजे, जिनमें से 134 स्वीकार कर लिए गए। 2019 से अब तक 36 अलग-अलग देशों से भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया है। इनमें वित्तीय धोखाधड़ी के अलावा हत्या, डकैती, यौन अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, संगठित अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और नकली मुद्रा कारोबार से जुड़े लोग शामिल हैं।

एफसीआरए और कुछ गंभीर सवाल, कानून सबसे ऊपर

हरबंश दीक्षित

विदेशी अंशदान को लेकर भारत में बहस नई नहीं है। विदेशी धन सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराता है, किंतु उसके साथ विदेशी प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और राष्ट्रीय हितों पर संभावित प्रभाव की चिंता भी जुड़ी रहती है। इसी संतुलन के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 विगत मार्च में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसी स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे निर्मित परिसंपत्तियों के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था करना है, जब किसी संस्था का एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द, समर्पित अथवा समाप्त हो जाए।

विधेयक के प्रस्ताव ने कुछ गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। मसलन, क्या एफसीआरए प्रमाणपत्र समाप्त होने पर विदेशी अंशदान से वर्षों पहले निर्मित परिसंपत्तियां भी सरकारी नियंत्रण में चली जाएंगी? यदि किसी परिसंपत्ति का निर्माण विदेशी और घरेलू, दोनों धन से हुआ हो, तो उसका क्या होगा? क्या नामित प्राधिकारी को परिसंपत्तियों के प्रबंधन और निस्तारण की व्यापक शक्ति अत्यधिक कार्यप्रभाव-विवेक को जन्म नहीं देगी? यदि प्रमाणपत्र के नवीनीकरण से इन्कार कर दिया जाए, तो क्या संस्था को पर्याप्त सुनवाई और प्रभावी अपील का अवसर मिलेगा? इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अनुच्छेद 14, 19, 21, 25, 26 और 300(ए) के उल्लंघन की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। विपक्ष के विरोध के बीच, केंद्र सरकार ने एफसीआरए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में कहा कि विदेशी अंशदान प्राप्त करना कोई पूर्ण या निरपेक्ष मौलिक अधिकार नहीं है। संसद विदेशी अंशदान के प्रवेश, उपयोग और प्रवाह को राष्ट्रीय हित में नियंत्रित कर सकती है। अनुच्छेद 19(1)(सी) नागरिकों को संघ अथवा संगठन बनाने का अधिकार देती है, किंतु इससे किसी संस्था को विदेशी स्रोत से धन पाने का असীमित अधिकार नहीं मिलता। कोई संस्था अपना सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अथवा परोपकारी कार्य जारी रख सकती है, लेकिन विदेशी धन प्राप्त करना वैधानिक शर्तों के अधीन है। इसी प्रकार इंडियन सोशल एक्शन फोरम बनाम भारत संघ (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने



विदेशी अंशदान के राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित करने को वैध माना। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक व आर्थिक कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को मात्र राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर विदेशी अंशदान से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्यायिक दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय हित और नागरिक समाज की वैध स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया। अनुच्छेद 19(4) के मुताबिक, भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक-व्यवस्था तथा नैतिकता के हित में संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नोएल हार्पर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एफसीआरए के कठोर नियामक ढांचे को इसी व्यापक दृष्टि से स्वीकार किया।

अब परिसंपत्तियों के प्रश्न पर विचार करें। यदि किसी संस्था को विदेशी अंशदान प्राप्त करने की वैधानिक अनुमति समाप्त हो गई है, तो उस अंशदान और उससे निर्मित परिसंपत्तियों की नियामक स्थिति को पूरी तरह अनिश्चित छोड़ देना भी व्यवस्था को अधूरा बना देगा। इसलिए, विधेयक में नामित प्राधिकारी के माध्यम से ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि इसे तत्काल और अपरिवर्तनीय अधिग्रहण के रूप में देखना उचित नहीं होगा। प्रस्तावित व्यवस्था में संपत्ति के अस्थायी निहितीकरण की अवधारणा है। यदि संस्था निर्धारित अवधि में नया प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेती है या उसका प्रमाणपत्र नवीनीकृत या पुनर्संथापित हो जाता है, तो परिसंपत्तियां और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान की वापसी की व्यवस्था है। स्थायी निहितीकरण बाद की अवस्था में आता है।

मिश्रित वित्तपोषण वाली परिसंपत्तियों के संबंध में भी सावधानी आवश्यक है। विधेयक विदेशी अंशदान से पूरी या आंशिक रूप से निर्मित परिसंपत्तियों को अपने दायरे में रखता है। इसलिए, यह कहना कि विदेशी धन का कोई

समाज को सत्ता हासिल करने और अपना भविष्य स्वयं लिखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने युवाओं को आरक्षण के खिलाफ बनाए जा रहे कथित प्रचार से भी सावधान किया। आनंद ने कहा कि आरक्षण गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता दूर करने का संवैधानिक माध्यम है। उन्होंने अपने समर्थकों से आगामी विधानसभा चुनाव को अधिकारों की लड़ाई का अवसर मानते हुए सक्रिय होने की अपील की।

इसी रणनीति के तहत आनंद ने नया नारा भी दिया, ‘इस बार वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को’। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। साफ है कि बसपा इस बार चुनावी लड़ाई को केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक आधार की वापसी की लड़ाई बनाना चाहती है। आकाश आनंद की आक्रामकता और युवाओं की भीड़ ने इस लड़ाई में फिटहाल एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि रैलियों में दिखाई दे रहा यह उत्साह वोटों में कितना बदलता है।

अंश लगते ही संस्था की संपूर्ण संपत्ति स्वतः सरकार की हो जाएगी, विधेयक की वास्तविक संरचना का परत्तीकरण होगा। वास्तविक सांविधानिक प्रश्न यह होगा कि ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में प्रक्रिया स्पष्ट, न्यायपूर्ण और अनुपातिक है या नहीं। अनुच्छेद 300(ए) के संदर्भ में भी यही कसौटी लागू होगी। संपत्ति से वंचित करना केवल विधि के प्राधिकार से संभव है। यहां संसद स्वयं वैधानिक आधार और प्रक्रिया निर्मित कर रही है। इसलिए परीक्षण यह होगा कि कानून का उद्देश्य वैध है या नहीं, प्रक्रिया न्यायपूर्ण है या नहीं और शक्ति का प्रयोग मनमाना तो नहीं है। केवल निहितीकरण की व्यवस्था होना अपने आप अनुच्छेद 300(ए) का उल्लंघन सिद्ध नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की आपत्ति का भी यही उत्तर है। प्रस्तावित व्यवस्था धर्म, जाति या विचारधारा के आधार पर भेद नहीं करती; इसकी कसौटी एफसीआरए प्रमाणपत्र और विदेशी अंशदान से संबंधित है। विदेशी स्रोत से प्राप्त धन को घरेलू धन से अलग नियामक श्रेणी में रखना तर्कसंगत है, क्योंकि उनके स्रोत और संभावित प्रभाव भिन्न हो सकते हैं। नोएल हार्पर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एफसीआरए के कठोर नियमन को मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं माना। धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 अवश्य महत्वपूर्ण हैं, किंतु धार्मिक स्वतंत्रता भी वित्तीय नियमन से पूर्णतः मुक्त नहीं है। यदि कानून का उद्देश्य धार्मिक आस्था या उपासना को नियंत्रित करना न होकर विदेशी अंशदान का नियमन है, तो मात्र किसी धार्मिक संस्था पर लागू होने से वह अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं बन जाता। प्रस्तावित व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि स्थायी रूप से निहित ऐसी परिसंपत्ति, जो उपासना-स्थल है, उसके धार्मिक चरित्र को बनाए रखा जाए। वास्तविक प्रश्न यह है कि भारत जैसा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य अपने सामाजिक क्षेत्र में विदेशी आर्थिक प्रभाव को किस सीमा तक स्वीकार करे और किस प्रकार उसकी निगरानी करे। इस पूरे विमर्श का सार है- राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हुए नागरिक समाज की वैध स्वतंत्रता का सम्मान, विदेशी आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित करते हुए विधि के शासन की सर्वोच्चता और नियमन की शक्ति के साथ न्यायपूर्ण प्रक्रिया की अनिवार्यता सुनिश्चित करना।

अपनी ही बोर्ड फसल काट रहे भयभीत डोनाल्ड ट्रम्प

राजेश बादल

डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी सीक्रेट एजेंसी और सेना की गोपनीय सलाह को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने सरेआम कहा कि पिछले महीने नाटो सम्मेलन में वे तुर्की गए थे। जब लौटने लगे तो उन्हें गोपनीय रिपोर्ट मिली कि ईरान उनके एयरफोर्स-वन विमान पर हमला कर सकता है। इसलिए वे अंकारा से तो एयरफोर्स वन की सीढ़ियां चढ़े। खड़े होकर उन्होंने हाथ हिलाकर मेजबानों का अभिवादन किया और अंदर चले गए।

फिर पीछे के कार्गो रास्ते से निकले और भोजन ले जाने वाले ट्रक में बैठकर अपनी सेना के विमान में बैठ कर सुरक्षित लौटे। अमेरिकी राष्ट्रपति के खास विमान में बैठे पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी उसी विमान से वापस अमेरिका गए। उनकी खिड़कियों के पदे जबवर बंद करा दिए गए थे ताकि कोई बाहर का दृश्य न देख सके।

वे ईरान के मारक दायरे से बाहर आ गए तो ब्रिटेन में फिर अपने एयरफोर्स वन में आकर बैठ गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए उनके सुरक्षा तंत्र ने ऐसा किया। यह अनोखी और दिलचस्प बात है कि संसार का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अपने ही सुरक्षा तंत्र की पोल खोल दे। आमतौर पर इस तरह की खुफिया योजनाएं तो कभी उजागर ही नहीं होतीं।

उनके सुरक्षा तंत्र को फिर कभी ऐसा कुछ करना पड़ा तो विमान से निकलने का तीसरा द्वार कहां से लाएंगे? इसके अलावा उनके दुश्मनों को यह भी पता होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति आसपास खड़े किसी दूसरे विमान से जा सकते हैं तो वह विमान भी निशाने पर रहेगा। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया? आगे बढ़ने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के मौजूदा मानसिकता को समझना होगा।

ईरान से जंग छेड़ने के सवाल पर तो अमेरिकी अवाम ही बहुमत से ट्रम्प के खिलाफ है। अब वह समझने लगी है कि ट्रम्प को बेवजह युद्ध छेड़ने अथवा उस तरह की परिस्थितियां बना देने की आदत है। वे खुद को सुखियों में बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वे प्रोपेगंडा वार भी छेड़ते रहते हैं। उनके झूठ तो प्रमाणित हो चुके हैं। यू-टर्न लेना उनका स्वभाव है और वे कभी भी अपना कोई फैसला पलट सकते हैं।

जब तब वे अपनी जान के खतरे की आशंका को



अमेरिका का राष्ट्रीय संकट बनाते रहे हैं। दो बार उन पर आक्रमण हुए। उन मामलों में भी उन्होंने यही नीति अपनाई। लेकिन अमेरिका की पढ़ी-लिखी आबादी में आज यह तथ्य रच्यो का विषय है कि दोनों हमले कहीं प्रायोजित तो नहीं थे। अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर उन्होंने लगभग सभी समर्थक राष्टों से फासला बढ़ा लिया है।

अब यूरोपीय देश उनके पिछलग्गू नहीं रहे। इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वे खिल्ली उड़ा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपमानित कर चुके हैं। जब से उन्होंने कनाडा को अमेरिका में विलय का प्रस्ताव दिया, तब से कनाडा छिटका हुआ है। कनाडा के साथ रिश्तों में वह पुरानी गर्मजोशी नहीं रही।

अलबत्ता भारत, चीन और रूस के मामलों में वे अभद्र और अमर्यादित नहीं बोलते, लेकिन उनकी सरकार का रवैया तीनों देशों के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। कह सकते हैं कि ट्रम्प के हवाई दावों की कलई धीरे-धीरे खुलती जा रही है। बड़े-बड़े बोल बोलकर भी रूस-यूक्रेन युद्ध को वे चौबीस घंटे में रकवा नहीं पाए। भारत-पाकिस्तान के बीच हिंसक झड़पें रोकने का नकली श्रेय वे कई बार ले चुके हैं।

भारत समेत अनेक देशों के अप्रवासियों को हथकड़ी-बेड़ी डालकर अमेरिका से बाहर करने का बेहद अपमानजनक रवैया वे अपना चुके हैं। अब सी फीसदी टैरिफ लगाकर वे लगभग आधे संसार की आबादी को नाराज करने पर तुले हैं। अमेरिका की आंतरिक वित्तीय स्थिति खस्ता है। वे उसे नियंत्रण में नहीं ला सके। कहते हैं कि अमेरिका का हथियार भंडार विराट और विशाल है।

लेकिन उनकी ही सरकार में बैठे सूत्र खुलासा करते हैं कि हथियारों का जखीरा अब खाली हो रहा है। ट्रम्प भीतर की खबरें लीक करने वालों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। कर्ज में बिंधा हुआ अमेरिका कैसे उस हथियार भंडार की भरपाई करेगा, यह शोध का विषय है। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी ही टीम के आला जानकारों और विश्वासपात्रों को एक-एक करके दरवाजा दिखाने का काम कर रहे हैं।

ईरान के साथ जंग छेड़कर ट्रम्प उस स्थिति का जा चुके हैं, जहां उनकी हालत सांप-छछूंदर जैसी हो गई है। न वे आगे जा सकते हैं और न पीछे हट सकते हैं। ईरान पर हमला करने संबंधी राष्ट्रपति के अधिकार सीमित करने वाला विधेयक

सिर्फ एक वोट से गिरा। ट्रम्प के अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद नाकली मुद्रा में खड़े हैं और डेमोक्रेट तो वैसे ही खिलाफ हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा सिरदर्द मध्यावधि चुनाव हैं। इनमें उनकी हार के 65 प्रतिशत आसार हैं। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट के 100 में से 35 स्थानों के लिए निर्वाचन होंगे। चुनाव पर्यवेक्षक ट्रम्प की दुर्बल स्थिति की आशंका जता रहे हैं। उनका मानना है कि इस हाल के लिए स्वयं डोनाल्ड ट्रम्प ही जिम्मेदार हैं।

उन्होंने अमेरिका में कारोबार की तरह लोकतंत्र को चलाया है। इसके दुष्परिणाम संसार का यह चौधरी भुगत रहा है। जानकार मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की जो बदहाली हुई है, उससे आगेले राष्ट्रपति के लिए चुनौतियां बेहद गंभीर हो सकती हैं। देश कितना ही प्रभावशाली और समृद्ध हो, लेकिन उसकी आर्थिक शक्ल बिगड़ चुकी है। अब ट्रम्प इससे बेहद भयभीत हैं।

वे अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हैं, मगर वे जितना छिपाने का प्रयास करते हैं, वह और उजागर होता जाता है। अपनी सुरक्षा के बारे में किसी राष्ट्रपति ने कभी गोपनीय जानकारियां साझा नहीं कीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं। यह केवल भयप्रस्त और असुरक्षित मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अवाम के बीच इतना अलोकप्रिय और हताशा से भरा नहीं रहा।

चीन की जमीन हड़पने की भूख कभी खत्म नहीं होगी

सनत जैन

अरूणाचल पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। 3 जिलों में चीन के सैनिक घुस गए हैं। भारतीय क्षेत्र में चीन ने स्थायी निर्माण कर लिये हैं। वहां की जनता शिकायतें कर रही है। इसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ। भारत सरकार ने कहा अरूणाचल भारत का हिस्सा था, आगे भी बना रहेगा। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद स्वतंत्रता के बाद से ही चल रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में चीन ने जिस सुनयोजित तरीके से भारत की सीमा से लगे हिस्सों पर कब्जा किया है। भारत सरकार की चुप्पी से यह मामला अब गंभीर हो गया है। चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद 8 दशकों से चल रहा है। चीन ने पहले भारत के साथ हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा देकर विश्वासघात किया और भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। 1962 के युद्ध में जब भारत आर्थिक एवं सामरिक रूप से बहुत कमजोर था। तत्कालीन भारत सरकार ने युद्ध लड़ा, और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। 1950 में तिब्बत पर चीनी नियंत्रण होने के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया। 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण दी, जिसके कारण 1962 का युद्ध भी हुआ। चीन और भारत के बीच युद्ध के बाद चीन ने भारत के साथ सीमा का विवाद जारी रखा। 1962 के युद्ध के बाद चीन की कभी हिम्मत नहीं हुई, वह भारतीय भूमि पर कब्जा कर सकती है। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद से चीन ने कभी भी भारत की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। सीमा विवाद को लेकर जरूर विवाद बना रहा। भारत सरकार ने भी चीन के साथ संबंधों को बनाए रखा, सीमा पर भारत हमेशा सतर्क रहा। पिछले कुछ वर्षों से चीन ने अरूणाचल और सीमावर्ती राज्यों में सुनियोजित तरीके से टुकड़ें-टुकड़े में कब्जा करने की कोशिश की। भारत

सरकार ने चीन की इस कार्रवाई का खुलकर विरोध नहीं किया। पिछले एक दशक में चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते चले गए। वर्तमान सरकार के चीन के साथ व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते बढ़ते रहे। इसके बाद भी सीमा पर तनाव बढ़ता चला गया। भारतीय सीमावर्ती राज्यों में चीन का कब्जा बढ़ने तथा सेना के साथ भिड़ंत होने, भारतीय सैनिकों की शहादत होने के बाद, भारत सरकार का संसद में यह कहना, चीन ना घुसा है, ना भारत की किसी भूमि पर कब्जा हुआ है। इसके बाद चीन को शह मिली, भारत के विदेश मंत्री का सार्वजनिक रूप से यह कहना, चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बहुत बड़ी है। हम चीन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों पर चीन ने अपनी घुसपैठ बढ़ा दी। अरूणाचल के तीन जिलों में चीनी सैनिक लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं। भाजपा सांसद और अरूणाचल के लोग कई बार इसकी शिकायत भारत सरकार और जिला प्रशासन से कर चुके हैं। इसके बाद भी भारत सरकार की चुप्पी सभी को आश्चर्यचकित कर रही है। चीन के साथ पिछले वर्षों में जिस तरह से संघ और भाजपा नेताओं का मेल-जोल बढ़ रहा है। चीन से आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है, इसके बाद भी भारत सरकार चुप है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होगा। वर्तमान सरकार भारतीय हितों की उपेक्षा कर रही है। अब तो अति हो गई है, अरूणाचल के तीन जिलों के नागरिक खुलकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। इतने संवेदनशील मामले में भारत सरकार की चुप्पी से भारत की सुरक्षा और सीमाएं दोनों ही खतरे में है। भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ केवल इसलिए कमजोर हो गए हैं, भारत अब चीन से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देशों ने चीन के साथ अपने रिश्ते बना लिए, भारत के साथ पड़ोसी देशों के रिश्ते काफी कमजोर हो गए हैं।

हर समस्या का समाधान है महावीर दर्शन

चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्म कल्याण है। उनके सिद्धांत बताते हैं कि वर्तमान के वर्तन (व्यवहार) को किस प्रकार से रखा जाए कि जीवन में शांति, मरण में समाधि, परलोक में सद्गति तथा परम्परे से परमगति पाई जा सके। मानवीय गुणों की उपेक्षा के इस समय में महावीर के कल्याण का दिन हमसे अपने जातीय भेद भुलाकर सत्य से साक्षात का संदेश देता है। भगवान महावीर ने अहिंसा की जितनी सूक्ष्म व्याख्या की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने मानव को मानव के प्रति ही प्रेम और मित्रता से रहने का संदेश नहीं दिया अपितु मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति से लेकर कीकीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी आदि के प्रति भी उसी मित्रता और अहिंसक विचार के साथ रहने का उपदेश दिया है। उनकी इस शिक्षा में पर्यावरण के साथ बने रहने की सीख भी है। आज जिस हिंसात्मक वातावरण और आपाधापी के बीच बच्चे बढ हो रहे हैं उसके कारण उनमें संयम का अभाव है। यह पीढी लक्ष्य से भटक रही है। ऐसे वातावरण में बढे हो रहे बच्चों से अपेक्षा रखना कि वे नैतिक राह पर चलेंगे ठीक नहीं। आज हमें समग्रता में महावीर की शिक्षाओं की बहुत जरूरत है ताकि हम इस धरा को सुंदर बना सकें।

बढती बुद्धि उन्नत कारोबार यही है बुधवार व्रत का उपहार

क्या आपका मन किसी काम में नहीं लगता क्या बार- बार किसी काम को करने से हतोत्साहित हो जाते हैं। या फिर व्यापार को लेकर आप हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। तो इन समस्याओं के छुटकारा पाने के लिए बुधवार का व्रत कर सकते हैं। यह व्रत स्त्री-पुरुष दोनों के लिए ही मंगलदायक होता है। इस व्रत को करने से आपकी बुद्धि में काफी इजाफा हो सकता है।

करने ये उपाय सर्वप्रथम नित्यकर्मों से मुक्त होकर बुध देवता के मंत्र से बुध त्वं बुद्धिजनको बोधदः सर्वदा नृणाम तत्त्वावबोधं कुरुषे सोमपुत्र नमो नमः ॥ उनका ध्यान करें। घर के इशान कोण में भगवान शिव या बुध का चित्र या मूर्ति कांस्य के बर्तन में स्थापित करना चाहिए। उनपर बेलपत्र, अक्षत, धूप और दीप जलाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। दिन हरे-पीले रंग के श्रेड वाले कपडे पहनने चाहिए। पन्ना रत्न धारण करना शुभ होता है। व्रत में हरी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। मूंग का हलवा, हरे फल, छोटी इलाइची का विशेष महत्व है।

दिन के व्रत की पूर्णाहुति सूर्यास्त के बाद एक बार फिर से बुध को धूप, दीप और गुड़, चावल एवं दही के भोग लगाने से होती है।इसके बाद प्रसाद वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में एक बार ही नमक रहित भोजन करना चाहिए। बुधवार का व्रत को विशाखा नक्षत्र में बुधवार के दिन है आरंभ करना चाहिए, जिसे 17 या 21 सप्ताह तक

से यात्रा प्रारंभ की। दो कोस की यात्रा के बाद उसकी गाडी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड के नीचे बैठकर जल लेने

उठा क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल-सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा ‘तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो’ मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा- ‘अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ।

लेकिन तुम मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो’ मधुसूदन ने कहा ‘तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड के नीचे बैठकर जल लेने गया था।’ इस पर उस व्यक्ति ने कहा- ‘अरे भाई झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो। नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकडवा दूंगा।’ दोनों एक-दूसरे से लडने लगे।

उन्हें लडते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों

को पकडकर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई- ‘मधुसूदन तूने संगीता के माता-पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है।’

मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की कि ‘हे भगवान बुधदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बडा गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा’ मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुधदेव की इस अनुकम्पा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाडी मिल गई। बैलगाडी का दूटा हुआ पहिया भी जुडा हुआ था।

दोनों समन बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन-यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुधदेव की कृपा से उनके यहां खुशियां बरसने लगीं।

मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की कि ‘हे भगवान बुधदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बडा गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा’ मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुधदेव की इस अनुकम्पा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाडी मिल गई। बैलगाडी का दूटा हुआ पहिया भी जुडा हुआ था।

दोनों समन बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन-यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुधदेव की कृपा से उनके यहां खुशियां बरसने लगीं।

आइये जाने मां दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी

हिंदू धर्म में मां दुर्गा की आराधना के लिए विशेष रूप से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को साल में दो बार मनाया जाता है। मां दुर्गा को कई नामों जैसे- काली, पार्वती, गौरी, सती, महामाया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा के रूप पार्वती को भगवान शिव की अधगनी माना जाता है। मां दुर्गा की उत्पत्ति की गाथा कुछ इस प्रकार है:

नवरात्री में आरती की थाली ऐसे सजाएं। एक बार की बात है, एक भैंसा दानव था, जिसे महिषासुर के नाम से जाना जाता था, जो बडा शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं का वध करना चाहता था, ताकि वह संसार में सर्वोच्च हो सके। इससे घबराकर सभी देवता, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्म के पास गए और अपनी बात कही। तब सभी ने सर्वसम्मति से अपनी शक्तियों से मिलाकर देवी दुर्गा का सृजन किया। देवी दुर्गा का सृजन सभी की शक्तियों को मिलाने से ही संभव था ताकि महिषासुर का वध किया जा सके। मां देवी दुर्गा का स्वरूप, बेहद आकर्षक है, उनके मुख में सौम्यता और स्नेह झलकता है। उनके दस हाथ हैं, जिसमें हर एक में एक विशेष शस्त्र



है। उन्हें हर भगवान और देवता ने कुछ न कुछ अवश्य दिया था, भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, भगवान वायु ने तीर आदि। देखिये दुर्गा पूजा की बेहतरीन तस्वीरें मां के कपडे और सवारी: मां दुर्गा की सवारी शेर है, जो हिमावत पर्वत से लाया गया था। इस प्रकार देवी दुर्गा को महिषासुर का वध करने के लिए बनाया गया। बाद में देवी दुर्गा ने महिषासुर को मार डाला।

इस स्वरूप को आप अक्सर तस्वीरों और मूर्तियों में देख सकते हैं। महिषासुर को देवी दुर्गा ने अपने शेर और शस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार मां दुर्गा, आज भी बुरी बाधाओं का वध करने के लिए पूजी जाती हैं। साल में चैत्र माह की नवरात्रि मुख्य होती है।

बालों में फूलों का गजरा लगाने का महत्व

भारत में आपको लडकियां और महिलाएं अपने बालों में फूल लगाएं जरूर मिल जाएंगी। खासतौर रर दक्षिण भारत में आपको हर लडकी बालों में एक या फूलों का गजरा लगाए दिख जाएंगी। रंग बरंगे फूल बालों को देखने में खूबसूरत ही नहीं बल्कि हर फूल की अपनी अगल-अलग परिभाषा होती है। उनके पीछे जरूर कोई मतलब छुपा होता है। हर फूल किसी ना किसी गुण से जुडा होता है। चाहे बात करें चमेली, गुलाबी, गुलदाउदी या गुलाब आदि फूलों की, इस सब में कोई ना कोई राज छुपा होता है। माना जाता है कि अगर घर की लडकी या महिलाएं इन फूलों को सिर में लगाएं तो घर में खुशहाली आती है। आइये जानते हैं इन फूलों के पीछे छुपे हुए राज को।

बालों में फूलों का गजरा लगाने का महत्व

- चमेली : चमेली अपनी खुशबू की वजह से फूलों की रानी के रूप में जानी जाती है। कोई खोहार चमेली के फूल का उपयोग केए बिना पूरा नहीं समझा जाता

है। यह समृद्धि और सौभाग्य का एक निशान है। इसलिए महिलाओं को आमतौर पर बालों पर चमेली के फूलों का गजरा पहने हुए देखा जाता है।

- गुलाब: गुलाब प्यार और जुनून का प्रतीक है। तो अगर कोई लडकी गुलाब का फूल बालों में लगाती है, तो इसका मतलब होता है कि वह या तो अपने प्यार को याद कर रही होती है या फिर प्यार के जुनून को दिखा रही है।
- गुलदाउदी: ये सुंदर से फूल खुशी को दर्शाते हैं। अगर एक लडकी बालों में गुलदाउदी पहनती है, तो वह अपने परिवार के लिए खुशी लाने के लिए सौचती है।
- गुडहर: यह फूल शक्ति का प्रतीक है इसलिए इससे काली देवी और अन्य रूपों की पूजा में प्रयोग किया जाता है।

फूलों का महत्व:फूलों का महत्व काफी प्राचीन है। भारत की हर संस्कृति में अलग अलग महिलाओं के लिये इन फूलों का महत्व एक दम जुडा है। भारत में लडकी का बालों में फूलों का गजरा

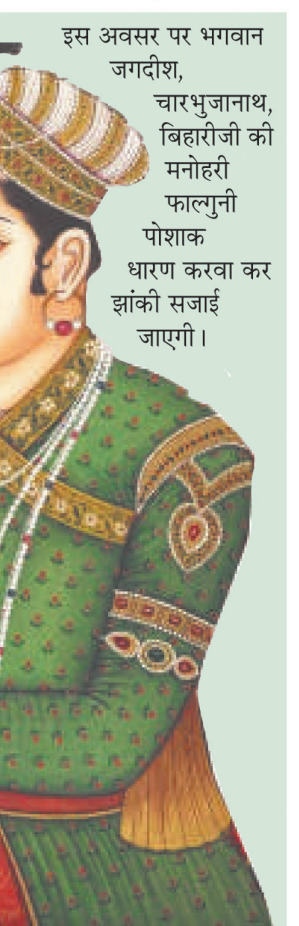


लगाने से मां लक्ष्मी घर में निवास करती हैं और वह घर को छोड कर कभी नहीं जाएंगी।

फेंगशुई प्रोडक्ट से जगा सकते हैं सोई किरमत्



मानते हैं कि यह वस्तुएं आपके सोई किस्मत को जगाकर आपके खुशहाल बना सकती हैं। हालांकि, कई जगह इन सामानों को भारतीय ज्योतिष से भी जोड कर देखा जाता है। जैसे कछुआ ना सिर्फ फेंगशुई में विशेष महत्व रखता है बल्कि ज्योतिष में भी इसका बेहद महत्व है। मान्यता है कि श्रीहरि विष्णु ने भी कछुआ रूप धारण कर समुद्र-मंथन के समय संसार की सहायता की थी। इसी तरह हाथियों को फेंगशुई के साथ भारतीय ज्योतिष में भी पुण्यकारी और लाभ देने वाला बताया गया है। फेंगशुई के सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए इसमें विश्वास होना बेहद जरूरी है।



आप सुख-समृद्धि लाने में काफी सहायक हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते समय दिल और दिमाग में इसके प्रति आस्था रखनी आवश्यक है, तभी यह मनोवांछित फल देते हैं। आज घर-घर में पाए जाने वाले लाफिंग बुद्धा, मनी प्लांट आदि फेंगशुई की ही देन है। फेंगशुई के जानकार

मानते हैं कि यह वस्तुएं आपके सोई किस्मत को जगाकर आपके खुशहाल बना सकती हैं। हालांकि, कई जगह इन सामानों को भारतीय ज्योतिष से भी जोड कर देखा जाता है। जैसे कछुआ ना सिर्फ फेंगशुई में विशेष महत्व रखता है बल्कि ज्योतिष में भी इसका बेहद महत्व है। मान्यता है कि श्रीहरि विष्णु ने भी कछुआ रूप धारण कर समुद्र-मंथन के समय संसार की सहायता की थी। इसी तरह हाथियों को फेंगशुई के साथ भारतीय ज्योतिष में भी पुण्यकारी और लाभ देने वाला बताया गया है। फेंगशुई के सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए इसमें विश्वास होना बेहद जरूरी है।

अगर विश्वास है तो तुच्छ माने जाने वाले बांस के पौधे भी आपके घर में पैसों की बारिश करा सकते हैं। फेंगशुई में मछलियों का महत्व होता है। मान्यता है कि मछलियां धन और समृद्धि लेकर आती हैं। मछलियों की उछलकूद देखने से मन को शांति मिलती है और यह अपने साथ सारे अपशकुन लेकर चली जाती हैं। हालांकि, इसे रखने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। फेंगशुई के अनुसार

घर में अगर जिंदा मछलियां रखनी हो तो आठ सुनहरी और एक काली मछली को मछलीघर में रखना चाहिए और अगर जगह की कमी हो तो आप दो मछलियों को रख सकते हैं। एक्वेरियम को रखने के भी कुछ नियम हैं जैसे इसे दरवाजे के पास या ठीक दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए। इसे घर की उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर कोई मछली मर जाती है तो यह अपशकुन नहीं है, यह संदेश होता है कि मछली घर पर आने वाली आपदा को अपने साथ लेकर चली गई। अगर घर में बडा एक्वेरियम रखने की जगह ना हो तो आप छोटा सा एक्वेरियम दो मछलियों वाला भी रख सकते हैं। यह प्यार का प्रतीक माना जाता है। साथ ही आप क्रिस्टल की बनावटी मछलियों का जोडा बेडरूम में रख सकते हैं।

गोल्डफिश को फेंगशुई के अनुसार सबसे अधिक पवित्र और संप्रदाता देने वाला माना जाता है। सोने की प्रतीत होने वाली यह मछली आपके जीवन में भी सोने की चमक बिखेर देगी। फेंगशुई एरोवाना मछली सबसे शुभ मछली माना जाता है। मान्यता है कि यह मछली अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, धन और शक्ति का प्रतीक है। फेंगशुई के अनुसार एरोवाना मछली बुरी शक्तियों को हटाती है। अगर

जिंदा एरोवाना मछली ना पाल पाएं तो आपको मुंह में सिक्का लिए हुए सुनहरी एरोवाना मछली की मूर्ति रखनी चाहिए।

आप जिंदा एरोवाना मछली ना पाल पाएं तो आपको मुंह में सिक्का लिए हुए सुनहरी एरोवाना मछली की मूर्ति रखनी चाहिए।

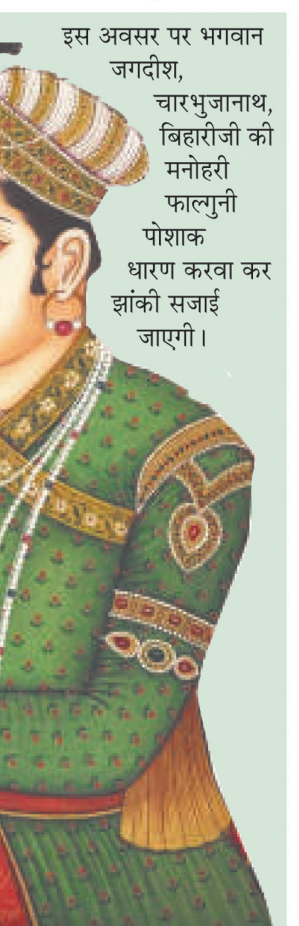
मान्यता है कि इस नींबू को अपने पास रखने वाले को समृद्धि मिलती तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में मंदिर प्रशासन ने एक पवित्र नींबू की नीलामी की। पांगुनी उतिराम त्योहार की एक रस्म के तहत की गई इस नीलामी में एक दंपती ने इसे 39,000 रुपये में खरीदा। तिरुवर्नै नल्लूर के बालातंडेउतपनी मंदिर में 11 दिनों तक उत्सव होता है। इसके आखिरी दिन भगवान मुरुगन के भाले पर लटकाए गए फलों को नीलाम करने की परंपरा है। गांव वालों की ऐसी मान्यता है कि इस नींबू को अपने पास रखने वाले को समृद्धि मिलती है और जिस दंपती के पास यह फल होता है, उन्हें संतान सुख मिलता है। इस साल दंपती जयरामन और अमरावती ने 39,000 रुपए देकर 'पवित्र' नींबू खरीद लिया। बाकी के आठ नींबू भी अच्छे दामों में बिके। कुल मिलाकर नौ नींबू 57 हजार 722 रुपए में बिके। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि किसी को नहीं पता कि यह मंदिर कब बनाया गया था। मंदिर उस जगह पर बना है, जहां दो पहाडियां मिलती हैं। काफी समय बाद गांव वालों का ध्यान इस मंदिर पर गया।

जब अकबर ने ली भगवान की परीक्षा, यह चमत्कार देख मान ली हार

शूरवीर और शहंशाह भी ईश्वर की शक्ति को नमन करते हैं। ऐसा ही एक बार अकबर के जीवन में भी हुआ था और उसने जगदीश महाराज के दरबार में शीश झुकाया। आगरा से अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत के जता समय बादशाह अकबर जब गोनेर के पास से गुजरा तो लोगों ने लक्ष्मी जगदीश महाराज की प्रसिद्धि के बारे में बताया। बादशाह ने भगवान की परीक्षा लेने की सोची और गोनेर की ओर कूच किया। उसने कहा कि यदि बिना मांगे मुझे मनचाहा प्रसाद एवं दर्शन हो जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो मंदिर को तोड दूंगा। उधर भगवान ने बादशाह की मंशा भांपकर अपने सेवक देवादास को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि एक भक्त मेरी परीक्षा लेने आ रहा है। उसे बिना मांगे

प्रसाद में घेवर देना और पंच पीर के दर्शन करवा देना। इस पर देवादास ने कहा कि भगवान हां तो किसी को घेवर बनाने भी नहीं आते। कैसे प्रसाद दूंगा इस पर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, सब प्रबंध हो जाएगा। जब अकबर गोनेर मंदिर पहुंचा तो सेवक देवादस ने बिना मांगे घेवर का प्रसाद देकर बादशाह को मंदिर में पंचपीर के दर्शन करा दिए। इससे बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। उसने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और शीश नवाया। तब से होली के दिन से भगवान को मालपुए एवं अन्य मिष्ठानों का भोग नहीं लगाया जाता। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा से पांच दिन लक्ष्मी जगदीश महाराज के केवल घेवर का ही भोग लगता है। रंगपंचमी के दिन भगवान को गर्भगृह से बाहार लाते हैं और गर्भगृह सहित पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता

है। लक्ष्मी जगदीश का मेला गोनेर स्थित श्री लक्ष्मी जगदीश भगवान का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल दूज पर लगने वाला वार्षिक लक्खी मेला शुक्रवार को आयोजित होगा। मंदिर के महंत हनुमान दास शर्मा एवं सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मेले में प्रदेशभर से श्रद्धालु आएंगे।



इस अवसर पर भगवान जगदीश, चारभुजानाथ, बिहारीजी की मनोहरी फाल्गुनी पोशाक धारण करवा कर झांकी सजाई जाएगी।

सम्मान और यश प्राप्ति की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य में होती है

सम्मान और यश प्राप्ति की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य में होती है, किंतु जिन कार्यों से सम्मान मिलना संभव होता है उन्हें करने के लिए बहुत कम लोग राजी होते हैं। झूठे सम्मान के लोभी मनुष्यों को अथक प्रयास करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है। जिस योग्यता पर यश मिलता और सम्मान बढ़ता है उसे बढ़ाया न जाए तो यह महत्वाकांक्षा अधूरी ही बनी रहेगी।

उचित योग्यता के अभाव में क्या किसी को सम्मान मिला भी है। योग्यता विलक्षणता, परिश्रम और अभ्यास से मिलती है। इसके लिए सबसे पहले अतुलनीय साहस उत्पन्न करना पडता है। साहस के बगैर वह शक्ति नहीं आती जो विघ्न

स्थिति में धैर्य स्थिर रख सके। सक्वेपरि स्थान प्राप्त करने के लिए घोर संघर्ष का सामना किए बिना कोई बच नहीं सकता। साहस से सहिष्णुता आती है, जिससे लोग हंसेते हुए उन कठिनाइयों को डोल जाते हैं। जब इस तरह का विशाल हृदय मनुष्य का बन जाता है तो यश स्वयं चलकर आपके पास आ जाता है।

कर्तव्य-बुद्धि का परिष्कारक ही गुणों की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। यश का लोभ कामना-पूर्ति में विलंब होते या विघ्न आने देखकर बीच में ही गिरा देता है, इसलिए उसे त्याज्य कहा गया है। यश की अभिलाषा आंतरिक हो और किसी आदर्श पर प्रतिरोपित हो तो ही मनुष्य कठिनाइयों के उच्च

शिखर पर चढता चला जाता है। कर श्रेष्ठता प्राप्त करने का अभ्यास आवेश या अंधानुकरण पर आधारित न हो अन्यथा अधिक देर तक उस सत्कर्म में टिके रहना संभव न होगा। विचार करें कि अपनी प्रकृति, स्थिति और शक्ति के अनुसार कौन-सी विशेषता सहज ही में प्रकट कर सकेंगे। दान, सेवा, भक्ति, चरित्र की निर्मलता, ब्रह्मचर्य आदि का चयन अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर करें।

विपरीत स्थिति और शक्ति से बढकर किए गए प्रयास प्रायः निष्फल होते हैं या फिर साहस इतना बुलंद हो कि प्रत्येक स्थिति की कठोरता को अंत तक सहन

ही गुणों का रचनात्मक विकास करें। सामान्य स्तर के व्यक्ति लिए भी जीवन में सम्मान प्राप्त करना एक सीधा सच्चा उपाय है। वह है वैर-भाव, ईर्ष्या-द्वेष और प्रतिशोध की भावना न रखना। सबके साथ प्रेम, दया, करुणा और सहदयता से रहकर यह स्थिति प्राप्त की जा सकती है।



पढ़ाया जाएगा पश्चिम बंगाल के निर्माता का इतिहास

कोलकाता। बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जनसंघ के संस्थापक डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन, राजनीतिक योगदान और बलिदान को राज्य के स्कूली और विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम में शामिल करने का बड़ा

एलान किया है।मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नवान्न में श्यामा प्रसाद मुखर्जी समिति की पहली उच्चस्तरीय बैठक के बाद बताया कि देश और राज्य के निर्माण में डा मुखर्जी के योगदान को लंबे समय तक राजनीतिक कारणों से दबाया गया। अब राज्य सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से ही नई पीढ़ी को उनके वास्तविक इतिहास से रूबरू कराएगी। पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ-साथ सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें भी प्रकाशित करने जा रही है। बीजेपी नेता तथागत राय द्वारा तैयार पुस्तक के संयुक्त प्रकाशन के अलावा जनशिक्षा प्रसार एवं पुस्तकालय सेवा विभाग को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।शिक्षा के अलावा राज्य सरकार ने कई अन्य प्रमुख घोषणाएँ भी की हैं।

एअर इंडिया ने सभी पायलटों के लिए अनिवार्य किया डोप टेस्ट

नई दिल्ली। फुकेत-दिल्ली उड़ान के एक पायलट के डोपिंग टेस्ट में मरिड्डुआना (गांजा) के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद एअर इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। एअर इंडिया ने अपने ग्रुप के सभी पायलटों का पूर्ण डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश आज से ही प्रभावी हो गया है। कर्मचारियों को भेजे गए औपचारिक पत्र में एअर इंडिया ने लिखा, जैसा कि आप जानते हैं, एअर इंडिया भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित सभी नियामक मानकों का पूरी तरह से पालन करती है। ये मानक यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख वैश्विक विमानन क्षेत्रों के नियमों के समान ही हैं।।ड्यूल, हर 30 मिनट मे फिर भी, हमें लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक कदम आगे बढ़ना आवश्यक है। इसीलिए, हमने अपने समूह के सभी पायलटों की पूरी जांच करने का निर्णय लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी गैर-अनुमत दवा या नशीले पदार्थ का सेवन न कर रहे हों। कंपनी ने आगे कहा, नियामक मानकों से आगे बढ़कर उठाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दी केंद्र और एफएसएएआई को अल्टीमेटम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार, 13 अगस्त को केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की कड़ी आलोचना की।सुप्रीम कोर्ट ने यह आलोचना ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले

पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर चेतावनी वाले लेबल लगाने में देरी को लेकर की। एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा, यह आपका आखिरी मौका है। अगली बार हम फैसला सुनाएंगे।जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र को अपना अंतिम फैसला रिकॉर्ड पर रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार कोई अंतिम फैसला नहीं लेती है, तो वह निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि यह मामला जन स्वास्थ्य, खासकर बच्चों की सेहत से जुड़ा है। कोर्ट ने पोषण से जुड़ी सख्त चेतावनियों को लागू करने में सरकार की हिचकिचाहट पर सवाल उठाए।

नेवी के हर युद्धपोत पर होगी ब्रह्मोस की तैनाती

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना 2030 तक ज्यादातर युद्धपोतों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगा देगी. ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता के बाद लगभग

20 जहाज लैस हैं. नए जहाजों में पहले से व्यवस्था है.भारतीय नौसेना अपने फंटेलाइन युद्धपोतों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक करूज मिसाइल लगाने की प्रक्रिया को तेज कर रही है. लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में बेड़े के बड़े हिस्से में इस मिसाइल को एकीकृत किया जाए. सूत्रों के अनुसार नौसेना 2030 तक प्रमुख युद्धपोतों पर ब्रह्मोस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. पिछले एक साल में छह से ज्यादा ब्रह्मोस सक्षम युद्धपोत बेड़े में शामिल हुए हैं जिससे कुल संख्या लगभग 20 पहुंच गई है. सभी नए कमीशन होने वाली जहाजें ब्रह्मोस सिस्टम से लैस होती हैं. मौजूदा जहाजों पर भी काम चल रहा है. यह मिसाइल समुद्री हमले की क्षमता को मजबूत बनाने वाला प्रमुख हथियार बन चुका है।

आजम-अखिलेश की दूरी मिटाएंगे शिवपाल?

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद आजम खान से सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने बुधवार को मुलाकात किया. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब यूपी में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है

और रामपुर में आजम खान के समर्थक इस बात को लेकर नाराज हैं कि आजम विरोधी नेताओं को सपा में एंट्री कराई जा रही है.उत्तर प्रदेश में बढ़ती चुनौती सरगमी के बीच समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात करने सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बुधवार को रामपुर पहुंचे. रामपुर की जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से शिवपाल यादव ने मुलाकात किया. इस दौरान शिवपाल और आजम के बीच एक घंटे तक बातचीत हुई. रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव सीधे रामपुर में उनके घर पहुंचे. यहां उन्होंने आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद तंजीन फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब आजम से मुलाकात की है. इसके बाद शिवपाल यादव रामपुर में मौलाना अली जौहर युनिवर्सिटी भी पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक कर रहे।

मानसून सत्र: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली। गुरुवार 13 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, जिसमें कामकाज बहुत कम हुआ। सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ और कई बिल बिना बहस के ही पास कर दिए गए। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मानसून सत्र बर्बाद हो गया और करोड़ों रुपये स्वाहा हो गया। अयोध्या के राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों रोज हंगामा कर रहे थे। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यानी 13 अगस्त को इसका अंतिम कार्यदिवस था।

लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। पूरा मानसून सत्र हंगामे और गतिरोध के भेंट चढ़ा दिया। रोज गोल-पोस्ट बदले इनकी मंशा कभी भी सदन को चलाने की थी ही नहीं...में समझती हूं इससे ज्यादा नकारात्मक विपक्ष हमने पहले कभी नहीं देखा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में छात्रों के विश्व प्रदर्शन पर कहा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। छात्रों के साथ भाजपा तन, मन और धन से लगी रहेगी। संसद सत्र पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, ये बहुत आपत्तिजनक है यहां पर पूरा माहौल खराब कर रखा हुआ है। दिन प्रतिदिन यहां पर माहौल ज्यादा खराब होता जा रहा है।

राहुल गांधी गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री को बात नहीं करने देंगे। ये किस तरह की बात करते हैं कहते हैं कि हमें जवाब नहीं चर्चा चाहिए, फिर कहते हैं हमें चर्चा नहीं जवाब चाहिए। ये सिर्फ बातों में उलझा रहे हैं इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब

स्टेल प्रमुख समाचार

15 अगस्त से शुरू होगा भारत का श्रीलंका दौरा

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने जा रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से यह सीरीज दोनों

टीमों के लिए बेहद अहम है। शुभमन गिल की कसानी में भारतीय टीम श्रीलंका का सामना करेगी, जबकि मेजबान टीम की कप्तान धनंजय डी सिल्वा के हाथों में होगी। भारत की नजर सीरीज जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी।

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से 19 अगस्त तक खेला जाएगा। यह मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, गॉल में होगा। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से 27 अगस्त तक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे। श्रीलंका में मैच की शुरुआत स्थानीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे होगी।

भारत और श्रीलंका दोनों के लिए यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उपलब्ध अंक तालिका के अनुसार भारत 52 अंकों और 48.15 प्रतिशत अंक के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 20 अंकों और 41.67 प्रतिशत अंक के साथ छठे स्थान पर है। ऐसे में दो टेस्ट मैचों के नतीजे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में दोनों टीमों की स्थिति पर बड़ा असर डाल सकते हैं।

शुभमन गिल की कसानी में भारतीय टीम के सामने श्रीलंका को उसके घर में हराने की चुनौती होगी। दूसरी तरफ धनंजय डी सिल्वा की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारत को कड़ी टक्कर देना चाहेगी। बुमराह और साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी के बावजूद भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी विकल्प हैं।



तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चले हैं। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। लोकसभा की कार्यवाही बृहत्पतिवार को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि, सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम् से पहले वह उस सत्र की कार्य उत्पादकता तथा उपलब्धियों का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम् के गायन के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को आरंभ हुआ था। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों में लगातार गतिरोध बना रहा।

सरकार ने कहा था कि वह छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है, हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा वह इन तीनों मांगों पर

सेंसेक्स 78000 के पार बंद निफ्टी में मामूली गिरावट

नईदिल्ली। टाटा ग्रुप और दमदार नतीजों वाले शेयरों के बूते बाजार में गुरुवार को निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुए हैं। बीएसई सेंसेक्स 113 अंकों की मजबूती के साथ 78,079 पर बंद हुआ, जबकि सुबह इंडेक्स की शुरुआत 78,111.91 पर हुई थी। कारोबारी सेशन में इंडेक्स ने 77,665.89 का निचला स्तर भी छुआ। एनएसई निफ्टी 50 मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। इंडेक्स 40 अंकों की गिरावट के साथ 24,395 पर बंद हुआ, जिसमें इंट्राडे में 24,431 का हाई भी बनाया था। बाजार में जोश भरने का काम टाटा ग्रुप के शेयरों ने की। निफ्टी 50 में शामिल टाटा कंस्ट्रुमर, टाटा मोटर्स के शेयर 2-2.6 फीसदी ऊपर बंद हुए हैं। आईटी दिग्गज टीसीएस भी 1 फीसदी से ज्यादा उछला।

मजबूत एआई मांग से लेनोवो इंडिया का राजस्व 18% बढ़ा

नई दिल्ली। लेनोवो इंडिया के राजस्व में चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़े एकीकृत समाधानों की मजबूत मांग से यह वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने भारत में अपने कारोबार से संबंधित राजस्व का विशिष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया है। लेनोवो इंडिया के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शैलेंद्र कट्याल ने कहा, लेनोवो इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 की मजबूत शुरुआत की है और पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में राजस्व सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ा है। यह प्रदर्शन व्यक्तिगत एआई और उद्यम एआई के लिए हमारे पूर्ण-स्तरीय हाइब्रिड एआई समाधानों की मजबूती, हमारी आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है।

चीन से एफडीआई पर भारत की सतर्कता जरूरी, आसियान और यूरोप से मिलते हैं सबक

अमिता वज्रा

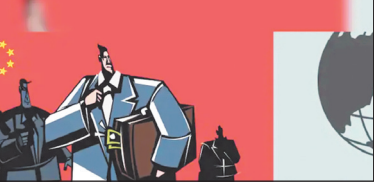
इस वर्ष के आरंभ में प्रेस नोट 3 में थोड़ी ढील देते हुए भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के नियमों को आसान बनाया। इसके तहत, जमीन से जुड़ी सीमा वाले देशों के विदेशी निवेशक, अ?धिकतम 10 फीसदी हिस्सेदारी के लिए सेक्टर से जुड़ी सीमाओं और शर्तों के अधीन ‘ऑटोमैटिक रूट’ के जरिए भारत में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही चीन से जुड़ी पूंजी को भी भारत में स्वतः निवेश की इजाजत मिल गई।

हालांकि निवेश हासिल करने वाली कंपनी को संबंधित ब्योरा उस क्षेत्र से तात्क्षुक रखने वाले मंत्रालय को देना होगा। इसके अलावा चुनिंदा विनिर्माण क्षेत्रों में पड़ोसी देशों से हासिल निवेश प्रस्तावों को प्रक्रिया पूरा करने के लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इनमें पूंजीगत वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत वस्तुएं और घटक,

पॉलीसिलिकॉन और इंगट-वेफर आदि शामिल हैं। इसके साथ यह शर्त भी लागू है कि बहुल हिस्सेदारी किसी भारतीय नागरिक या भारतीय-स्वामित्व वाली इकाई के पास हो रहे। यह छूट रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर लागू नहीं होती।

इस बदलाव से उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनएसी) के लिए नियामकीय नरमी की तत्व जुड़ता है जिनमें मामूली चीनी हिस्सेदारी है, या उन संयुक्त उपक्रमों के लिए जिनमें चीनी संस्थाओं की गैर नियंत्रक हिस्सेदारी है। इस संदर्भ में पिछले दशक में विकासशील और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं में चीनी एफडीआई के कुछ प्रमुख रूझानों को उजागर करना अहम है।

पिछले दशक में चीनी एफडीआई में शुरुआती उछाल मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा ट्रंप के पहले शासनकाल के दौरान लगाए गए ऊंचे शुल्क के कारण था। यह प्रवृत्ति कमजोर



घरेलू उपभोग खर्च और उभरती अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता के चलते और तेज हुई। हाल ही में यानी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान जबवही शुल्क लगाने और निर्यात के ट्रांसशिपमेंट की कड़ी जांच से इसे और बढ़ावा मिला। शुरुआती वर्षों में चीनी एफडीआई मुख्य रूप से आसियान में नियरशोरिंग (उत्पादन या सेवाओं को किसी पड़ोसी देश में स्थानांतरित करना) की वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जोवीसी) विविधीकरण रणनीति का अनुसरण करता था।

खासकर वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया में। जैसे-जैसे आसियान

श्रीराम प्रॉपर्टीज का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 46% घटा

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी श्रीराम प्रॉपर्टीज का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 46 प्रतिशत घटकर 11.04 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 20.59 करोड़ रुपए था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि सीमाक्षीधीन अवधि में कुल आय मामूली बढ़कर 271.04 करोड़ रुपए हो गई जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 261.54 करोड़ रुपए थी। कंपनी के परिचालन खर्च और कर व्यय अप्रैल-जून तिमाही में बढ़े। इसके अलावा, संयुक्त उद्यम वाली परियोजनाओं में भी कंपनी को नुकसान हुआ। परिचालन प्रदर्शन के मोर्चे पर श्रीराम प्रॉपर्टीज की पहली तिमाही में बिजली बुकिंग 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 484 करोड़ रुपये रही। श्रीराम प्रॉपर्टीज के चेयरमैन ने कहा, हमने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत मजबूत प्रदर्शन के साथ की है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में 34.3% बढ़ा : सियाम

नई दिल्ली। घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 34.3% बढ़कर 4,57,810 इकाई हो गई। उद्योग संगठन सियाम ने बृहत्संयोजक को यह जानकारी दी। यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई 2025 में 3,40,772 इकाई रही थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) के बयान के अनुसार, पिछले महीने कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री 22.6% बढ़कर 19,23,483 इकाई हो गई जबकि जुलाई 2025 में यह 15,69,120 इकाई थी। सियाम के अनुसार, तिपहिया वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में 33.4% बढ़कर 92,560 इकाई हो गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 69,403 इकाई थी। सियाम के महानिदेशक ने कहा, भारतीय वाहन उद्योग ने जुलाई में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार



श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़

संस्कृति, लोककला और परंपराओं की जीवंत धरती



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और जनजीवन की सादगी के लिए देशभर में विशेष पहचान रखता है। यहां की संस्कृति केवल त्योहारों, लोकगीतों और लोकनृत्यों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन, व्यवहार और सामाजिक मूल्यों में भी गहराई से रची-बसी है। आदिवासी परंपराएं, लोककलाएं, पारंपरिक रीति-रिवाज और प्रकृति के प्रति सम्मान इस प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत बनाते हैं। छत्तीसगढ़ की यही विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहरों में एक अलग स्थान प्रदान करती है, जहां हर परंपरा जीवन को जोड़ने और समाज को मजबूत बनाने का माध्यम बनती है।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र द्रविण कौसल के नाम से प्रसिद्ध था। रामायण काल से जुड़े अनेक प्रसंग यहां की धरती से संबंधित माने जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का लंबा समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। यही कारण है कि यहां की लोक आस्था, धार्मिक परंपराओं और लोकगीतों में रामकथा का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। समय के साथ यहां आदिवासी संस्कृति, ग्रामीण जीवन और विभिन्न समुदायों की परंपराओं ने मिलकर एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान का निर्माण किया है।

लोकगीत और लोकभाषा की मिठास

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का सबसे सशक्त पक्ष यहां की लोकभाषा और लोकगीत हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की मिठास और सहजता लोगों के व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। यहां बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं और लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा सरगुजिहा, हल्बी, गोंडी, कुडुख और अन्य जनजातीय बोलियां भी प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती हैं। ग्रामीण परिवेश में आज भी ददरिया, सुवा गीत, करमा गीत और पंथी गीतों की गूंज सुनाई देती है। इन गीतों में प्रेम, प्रकृति, श्रम, सामाजिक संबंध और लोक आस्था का सुंदर चित्रण मिलता है।

लोकनृत्य: हमारी पहचान

प्रदेश के लोकनृत्य यहां की सांस्कृतिक पहचान को विशेष रूप से दर्शाते हैं। लोकनृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामुहिक जीवन, सामाजिक उत्सव और धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है।
❖ **पंथी नृत्य:** सतनामी समाज की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है।
❖ **राउत नाचा:** दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोकनृत्य है।
❖ **करमा नृत्य:** आदिवासी समाज में प्रकृति और फसल उत्सव से जुड़ा हुआ है।
❖ **सुवा नृत्य:** महिलाओं द्वारा किया जाने वाला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बस्तर: जनजातीय संस्कृति की अनुपम धरोहर

बस्तर अंचल की जनजातीय संस्कृति छत्तीसगढ़ की आत्मा मानी जाती है। यहां रहने वाले गोंड, मुरिया, हल्बा, भतरा, माड़िया और अन्य जनजातीय समुदाय आज भी अपनी पारंपरिक जीवनशैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए हैं। जनजातीय समाज प्रकृति को जीवन मानता है। जंगल, नदी, पहाड़ का संसाधन नहीं, बल्कि आस्था और जीवन के प्रतीक हैं।

पारंपरिक कला और हस्तशिल्प

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प भी देशभर में विशेष पहचान रखते हैं। बस्तर की ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है। धातु से बनी पारंपरिक मुर्तियां और कलात्मक वस्तुएं यहां की अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण हैं। इसी प्रकार लकड़ी और बांस से निर्मित हस्तशिल्प ग्रामीण और जनजातीय कारीगरों की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। मिट्टी के बर्तन, लोक चित्रकला, पारंपरिक आभूषण और गोदना कला भी प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।



त्योहार: संस्कृति के जीवंत रंग

छत्तीसगढ़ के त्योहार यहां की लोक संस्कृति को और अधिक जीवंत बनाते हैं। यहां के अधिकांश पर्व कृषि, प्रकृति और लोक आस्था से जुड़े हुए हैं।
❖ **हरेली:** किसानों का प्रमुख त्योहार, कृषि उपकरणों की पुजा
❖ **पोला पर्व:** बैलों और कृषि संस्कृति के सम्मान का प्रतीक
❖ **तीजा:** महिलाओं का प्रमुख पर्व, सुख-समृद्धि की मंगलकामना छेरछेरा सामाजिक समरसता और अन्नदान की परंपरा
इन पर्वों के दौरान लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजन पूरे वातावरण को उत्सवमय बना देते हैं।



बस्तर दशहरा की वैश्विक पहचान

बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं का सबसे भव्य उदाहरण माना जाता है। यह देश का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव है, जो लगभग 75 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति की आराधना, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक सहभागिता का अनुठा संगम है। मां दत्तेश्वरी की पूजा के साथ निकलने वाली विशाल रथयात्रा यहां की सांस्कृतिक आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार दुनिया के इस सबसे लंबे समय तक चलने वाले लोक उत्सव को वैश्विक पहचान दिला रही है।



खान-पान: संस्कृति का अभिन्न हिस्सा

छत्तीसगढ़ का खान-पान भी यहां की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। चावल यहां का प्रमुख भोजन है। फरा, चीला, अंगाकर रोटी, ठेठरी- खुरमी, देहरौरी और ये बोरे बासी जैसे पांरिक व्यंजन प्रदेश की विशेष पहचान हैं। बोरे वासी को श्रमशील जीवनशैली और ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। प्राकृतिक और सादगीपूर्ण भोजन यहां के लोगों के स्वास्थ्य और जीवनशैली से गहराई से जुड़ा हुआ है।



संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति

- ❖ पर्यटकों को आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन नीति तैयार की गई है।
- ❖ इस नीति में पर्यटन स्थल में आधुनिक और विकसित सुविधाओं के लिए निवेश करने वाले उद्यमियों को अनेक प्रकार से सुविधाएं दी जा रही है।
- ❖ विशेषतौर पर बस्तर अंचल में पर्यटन, सुविधाओं के विस्तार के लिए टूरिज्म सर्किट भी विकसित किया जा रहा है।

- ❖ इसके माध्यम से बस्तर अंचल के पर्यटन स्थलों में बेहतर कनेक्टिविटी विकसित होगी।
- ❖ पर्यटन नीति में ईको-टूरिज्म, एथनिक (आदिवासी), एडवेंचर और वेलेनेस टूरिज्म को प्राथमिकता दी गई है।
- ❖ होम स्टे पॉलिसी के माध्यम से स्थानीय समुदाय को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है।

- ❖ छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है।
- ❖ धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 60 देशों के 20 पर्यटन गांवों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है।
- ❖ भारत सरकार ने धुड़मारास गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के पुरस्कार से सन्मानित किया है।



जशपुर का मधेश्वर पहाड़ 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में

जशपुर जिले के मयाली गांव से 35 किमी दूर स्थित मधेश्वर पहाड़ को 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में दर्ज किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई पहचान मिली है। मधेश्वर पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय होता जा रहा है। केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो विशेष रूप से मधेश्वर महादेव धाम और पहाड़ के धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र के विकास में खर्च की जा रही है।

